THE UNCOVERED UPDATE
सच जो छुपा था, अब सामने है

हिन्दी समाचार पत्र

द अनकवर्ड अपडेट

कवर के पीछे की खबर | Digital Edition | RJHIN/25/A4779

www.hpnews.in/www.tniawaaz.in | जयपुर, शुक्रवार 20 नवंबर, 2026 | » वर्ष: 01 » अंक: 26 » पृष्ठ: 8 » मूल्य: 2.00 रू.

एक नजर



वेतन बढ़ाने से उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी:अनुराधा ठाकुर

नई दिल्ली (एजेंसी)। आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने गुरुवार को भारतीय उद्योग जगत से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे उपभोक्ता मांग को बल मिलेगा और देश की आर्थिक वृद्धि को लंबे समय तक मजबूती मिलेगी। फिक्की (एफआईसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि अप्रैल से निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं और अब यह सुधार कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रहकर व्यापक रूप लेता दिख रहा है।



पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में देश में ईंधन के घटे दाम : हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में देश में ईंधन के दामों में कटौती हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के साइडलाइन में मीडिया से बातचीत में पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने के कारण बीते चार वर्षों में देश में ईंधन की कीमतों में कमी देखने को मिली है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसका उद्देश्य ईंधन को सभी लोगों की पहुंच में बनाए रखना था।



गुंडों को ढूंढकर ऐसी सजा देंगे, कई पीढ़ियां याद रखेंगी: मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान एक किशोर की मौत पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे निर्मम हत्या करार दिया है। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि सड़क पर अराजकता फैलाने वाले गुंडों को ढूंढ़ निकालें और उन्हें ऐसी कठोर सजा दिलाएं, जिसे उनकी कई पीढ़ियां याद रखें। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुधवार को समाजवादी पार्टी का एक रोड शो था। उन्होंने एक नाबालिग लड़के को अपने रोड शो का शिकार बना दिया। सपा गुंडागर्दी, दंगे, अराजकता और कर्फ्यू की प्रायः है।

जयपुर में 4 दिसंबर से होगा लोकमंथन-2026

'हम भारत के लोग' रहेगी थीम; मुख्यमंत्री ने किया भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में लोकमंथन-2026 की स्वागत समिति की बैठक को भी संबोधित किया

तीन दिवसीय लोकमंथन-2026 का विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया





जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में तीन दिवसीय लोकमंथन-2026 का गुरुवार को विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीएम ने हवन में पूर्णाहुति अर्पित की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी आदि मौजूद रहे। 'हम भारत के लोग' थीम पर आधारित लोकमंथन का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने जवाहर कला केंद्र में लोकमंथन-2026 की स्वागत समिति की बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गौरवशाली धरा पर लोकमंथन-2026 का आयोजन होना प्रदेश के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत, लोक कलाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है।

'हम भारत के लोग' थीम पर होगा राष्ट्रीय विमर्श

इस बार लोकमंथन की थीम 'हम भारत के लोग' है। आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं और राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक विमर्श करना है। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले विचारक, चिंतक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी और संस्कृतिकर्मी भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, लोकजीवन और राष्ट्रीय चिंतन के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा करेंगे।



भारतीय संस्कृति और समसामयिक विषयों पर होगा मंथन



उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी भूमि पूजन कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि वीरभूमि राजस्थान की गौरवशाली धरा पर भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चिंतन और समसामयिक विषयों पर सार्थक विमर्श के उद्देश्य से लोकमंथन-2026 का आयोजन होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा- आयोजन में देशभर के विचारक, चिंतक, साहित्यकार और राष्ट्रचिंतक एकत्रित होंगे। वे भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और भविष्य की संभावनाओं पर विचार साझा करेंगे। भूमि पूजन और स्वागत समिति की बैठक के दौरान प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक और लोकमंथन स्वागत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जे. नंदकुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघचालक और स्वागत समिति के उपाध्यक्ष डॉ. रमेश अग्रवाल, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार आदि मौजूद रहे।



आठ साल बाद फिर शाही सफर पर लौटा अमेरिकी दंपती

66 विदेशी मेहमानों के साथ पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची जयपुर, पारम्परिक अंदाज में पर्यटकों का स्वागत हुआ

जयपुर(नि.सं.)। आठ साल पहले यानी 2018 में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में सफर कर चुके एक अमेरिकी दंपती ने इस बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ राजस्थान की शाही यात्रा की योजना बनाई। इसके लिए अमेरिकी नागरिक नील हरीश अमीन ने पैलेस ऑन व्हील्स की पूरी ट्रेन ही चार्टर बुक कर ली। इस शाही सफर के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से कुल 66 विदेशी मेहमान जयपुर पहुंचे। गुरुवार को गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर इन पर्यटकों का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया गया।

जयपुर- जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना आज

जिला परिषद के 57 वार्डों की काउंटिंग के लिए 98 टेबिल लगाई; 22 पंचायत समितियों के लिए 22 रूम

जयपुर। जयपुर जिला परिषद और पंचायत समितियों सदस्यों के लिए कल वोटो की काउंटिंग होगी। भवानी निकेतन परिसर में मतगणना होगी। हर वार्ड की ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होने से पहले उसी वार्ड के पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए 5 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 वोटिंग काउंटिंग रूम बनाए है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया- जिला परिषद सदस्यों के वोटो की काउंटिंग के लिए कुल 5 कमरे निर्धारित किए हैं। सभी 57 वार्डों की मतगणना के लिए कुल 98 टेबल निर्धारित की गई हैं।

वार्ड संख्या 1 से 10 तक के 10 वार्डों की काउंटिंग होगी, जिसके लिए 18 टेबल लगाई जाएगी। इसी तरह वार्ड संख्या 15 से 26 तक के 12 वार्डों के लिए 19 टेबल, वार्ड संख्या 27 से 37 तक के 11 वार्डों के लिए 21 टेबल और वार्ड संख्या 38 से 50 तक के 13 वार्डों के लिए 20 टेबल निर्धारित की हैं। इसी तरह वार्ड संख्या 11 से 14 और51 से 57 तक के कुल 11 वार्डों की काउंटिंग के लिए 20 टेबल निर्धारित की गई हैं। 22 पंचायत समिति सदस्यों की काउंटिंग के लिए 22 रूम तैयार किए है।



मोदी बोले:किसानों-कारोबारियों को गाली देने से देश नहीं बढ़ता

हमने 12 साल में इकोनॉमी बदली, राहुल ने कहा था- भारत आर्थिक संकट की ओर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि किसानों और कारोबारियों को गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में भारत की इकोनॉमी बदली है और 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम का यह बयान राहुल गांधी के आरोपों के एक दिन बाद आया है। राहुल ने बुधवार को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियां हैं।



50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले

पीएम ने कहा कि 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।



ग्लोबल मार्केट के अवसरों का फायदा उठाएं

प्रधानमंत्री ने कारोबारियों से घरेलू बाजार तक सीमित न रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को दूसरे देशों की जरूरतों और ग्राहकों की पसंद समझकर उत्पाद तैयार करने चाहिए। मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस के जरिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने कारोबारियों से बिना झिझक अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव देने को कहा। सरकार उनके साथ खड़ी है।

64 विला-कॉटेज खरीद मामले में आईएएस-शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ीं

हाईकोर्ट का जांच पर रोक लगाने से इनकार, कहा- पहले सरकार का जवाब आने दें



जयपुर। 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में IAS शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार सुबह 10:40 बजे शिखर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा है। अब 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। शिखर ने 17 नवंबर को अपने खिलाफ एसीबी जांच को चुनौती दी थी।

केरल हाईकोर्ट बोला- बच्चे को गोद लिया हुआ कहना गलत

सरकारी कागजों में सिर्फ बेटा-बेटी लिखें, वे भी माता-पिता के अपने बच्चे, समान दर्जा मिले

तिरुवनंतपुरम(एजेंसी)। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के आगे गोद लिया हुआ बेटा या गोद ली हुई बेटी न लिखा जाए। सरकारी दस्तावेजों में उसे सिर्फ बेटा या बेटी ही लिखा जाए।

एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती, भूपेंद्र यादव ने निगरानी बढ़ाने और नियमों के कड़े पालन के दिए निर्देश



नई दिल्ली। भूपेंद्र यादव ने तुर्की के अंताल्या से वर्चुअली एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और रोजाना निगरानी रखें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सर्दियों के मौसम में ठोस और निरंतर कार्रवाई की।

जयपुर एयरपोर्ट

जयपुर एयरपोर्ट की 7-फीट की दीवार फांदकर अंदर घुसा युवक

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह टर्मिनल-2 के पास 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल फांदकर एक युवक एयरपोर्ट परिसर में घुस गया। CISF के जवानों ने उसे पकड़कर एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नूखा के निवासी नंदा दुलाल दास (40) के रूप में हुई। CISF के ASI श्रवण कुमार की शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज किया गया।

लकड़ियों के सहारे दीवार पर चढ़ा, नुकीले तारों के बीच से कूदा

मामले की जांच कर रहे एयरपोर्ट थाने के ASI रामराज ने बताया- गिरफ्तार आरोपी नंदा दुलाल पश्चिम बंगाल में रहकर मजदूरी करता है। वह पश्चिम बंगाल से घूमते हुए जयपुर आ गया। मंगलवार रात जयपुर एयरपोर्ट के पास शराब पी।

रिपोर्ट

भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटेगी, अमेरिका में दोगुनी हो जाएगी

इस्लाम 2035 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा

नई दिल्ली(एजेंसी)। वैश्विक स्तर पर धार्मिक आबादी में हो रहे बदलावों को लेकर अमेरिका की प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक, दुनिया की आबादी 2050 तक 9.30 अरब पहुंच सकती है, जो 2010 में करीब 6.90 अरब थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 के मुकाबले 2050 तक मुस्लिम आबादी करीब 73त्न बढ़ सकती है। यानी मुसलमानों की आबादी 1.6 अरब से बढ़कर लगभग 2.76 अरब हो जाएगी। 2020 से 2050 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 17.6 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटने का अनुमान है। इसके बावजूद 2070 तक हिंदू भारत की कुल आबादी के तीन-चौथाई से ज्यादा बने रहेंगे। इस दौरान अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो जाएगी।

मुस्लिम महिलाओं के औसतन बच्चों की संख्या ज्यादा

पिछले कुछ दशक में भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। हालांकि, मुस्लिम महिलाओं के औसतन बच्चों की संख्या हिंदू महिलाओं से अधिक है। इसके अलावा भारत में मुस्लिम आबादी का आयु वर्ग भी अपेक्षाकृत युवा है। इन दोनों कारणों



से आने वाले दशकों में देश की आबादी में मुस्लिमों का अनुपात बढ़ने और हिंदुओं की हिस्सेदारी में मामूली कमी आने का अनुमान है। प्यू रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। फिलहाल दुनिया में 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुस्लिम हैं।

अनुमान है कि 2035 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 2.57 अरब और ईसाई आबादी 2.52 अरब हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। 2020 से 2025 के बीच मुस्लिम महिलाओं में प्रति महिला औसतन 3.1 बच्चे पैदा हुए, जबकि ईसाई महिलाओं में यह आंकड़ा 2.5 और अन्य धर्मों में 1.6 रहा। प्यू के अनुमान के मुताबिक, 2070 तक दुनिया में मुस्लिमों की आबादी 3.6 अरब से ज्यादा हो सकती है।

जयपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने किया सुसाइड

पेड़ पर फंदे से लटका मिला; रातभर ढूंढते रहे परिजन

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने सुसाइड कर लिया। गुरुवार सुबह पेड़ पर फंदे से उसका शव लटका मिला। पुलिस ने कांवटिया हॉस्पिटल में शव का पोस्टमॉर्टम करवाया। पुलिस जांच में सामने आया कि रातभर उसको परिजन ढूंढ रहे थे। पुलिस की ओर से मर्ग दर्ज कर सुसाइड के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

THE UNCOVERED UPDATE
सच जो छुपा था, अब सामने है
हिन्दी समाचार पत्र
जयपुर अपडेट
गुलाबी शहर की हर खबर
| Digital Edition |
RJHIN/25/A4779
शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026

पंचायतीराज चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को, भवानी निकेतन में सुबह 8 बजे से होगी शुरू

जिला परिषद के 57 वार्डों एवं 22 पंचायत समितियों के सदस्य पदों की होगी मतगणना

कुल 243 टेबलों पर होगी मतगणना, प्रत्येक टेबल पर नियुक्त रहेंगे दो कार्मिक

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जयपुर में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जयपुर संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद के 57 वार्डों की मतगणना के लिए 5 कक्षों में 98 टेबल तथा जिले की 22 पंचायत समितियों के सदस्य पदों की मतगणना के लिए 22 कक्षों में 145 टेबल निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार कुल 243 टेबलों पर मतगणना करवाई जाएगी। पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के लिए 2,098 मतदान केंद्रों की ईवीएम निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक एवं एक मतगणना सहायक नियुक्त रहेंगे। मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य में नियुक्त कार्मिकों को प्रातः 6 बजे तक मतगणना स्थल पर पहुंचना होगा। उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं मतगणना अभिकर्ताओं को अधिकृत पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में एक समय में एक वार्ड की मतगणना होगी। संबंधित वार्ड की ईवीएम की गणना प्रारंभ करने से पहले उसी वार्ड के डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना परिसर में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों तथा अधिकृत कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मोबाइल फोन, पेजर आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना कार्मिकों एवं अभिकर्ताओं के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थल पर पार्क करने तथा मोबाइल फोन वहीं सुरक्षित रखने के बाद मतगणना स्थल में प्रवेश करना होगा। मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति केवल इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े अधिकृत व्यक्तियों को होगी।

उन्होंने बताया कि मतगणना के परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाए जाएंगे। मतगणना से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

संजना जाटव, दिव्या मदेरणा को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया:राजस्थान कांग्रेस के तीनों सह-प्रभारी हटाए, चार नए सह-प्रभारी सचिव लगाए



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस के तीनों सह-प्रभारी सचिवों को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह चार नेताओं को राजस्थान में सह-प्रभारी सचिव लगाया गया है।

राजस्थान के 6 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया है, जबकि सांसद संजना जाटव, दिव्या मदेरणा सहित तीन नेताओं को पद से हटाया है। राजस्थान कांग्रेस के सह-प्रभारी सचिव चिरंजीव राव, ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान को राष्ट्रीय सचिव व सह-प्रभारी पद से हटा दिया है।

राजस्थान में चार राष्ट्रीय सचिवों को सह-प्रभारी लगाया है। कांग्रेस नेता विश्व विजय सिंह, पलक वर्मा, मनोज बागड़ी और पोरलक खारते को राजस्थान के सह-प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी दी है।

राजस्थान से 6 राष्ट्रीय सचिव

राजस्थान से 6 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। सेवा दल के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, विधायक डूंगर राम गेदर, पूर्व विधायक धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, जगदीश जांगिड़ और रेहाना रियाज को राष्ट्रीय सचिव बनाकर राज्यों में सह-प्रभारी बनाया है। हेम सिंह शेखावत और डूंगर राम गेदर को पहली बार जिम्मेदारी दी गई है।

दिव्या, संजना सहित तीन राष्ट्रीय सचिवों को हटाया

सांसद संजना जाटव, पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और विजय जांगिड़ को राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया है। दिव्या मदेरणा के पास जम्मू-कश्मीर के सह-प्रभारी सचिव की जिम्मेदार थी। इस बदलाव को लेकर सियासी हलकों में चर्चा हो रही है।

धीरज गुर्जर को जम्मू-कश्मीर, जगदीश जांगिड़ को यूपी का सह-प्रभारी बनाया

राजस्थान से राष्ट्रीय सचिव बनाए गए 6 नेताओं को राज्यों में सह-प्रभारी बनाया गया है। हेम सिंह शेखावत को गुजरात, धीरज गुर्जर को जम्मू-कश्मीर, दानिश अबरार को दिल्ली, जगदीश जांगिड़ को उत्तर प्रदेश, डूंगर राम गेदर को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और रेहाना रियाज को महाराष्ट्र के सह-प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी दी है।

जयपुर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना आज:जिला परिषद के लिए 98 टेबल लगाई; 22 पंचायत समितियों के लिए 22 रूम

द अनकवर्ड अपडेट



जयपुर। मतगणना से पहले भवानी निकेतन पर वाहनों की लंबी लाइन। प्रत्याशी व उनके समर्थकों का आना भी शुरू हो गया है। - मतगणना से पहले भवानी निकेतन पर वाहनों की लंबी लाइन। प्रत्याशी व उनके समर्थकों का आना भी शुरू हो गया है।

जयपुर जिला परिषद और पंचायत समितियों सदस्यों के लिए आज भवानी निकेतन परिसर में मतगणना होगी। हर वार्ड की ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होने से पहले उसी वार्ड के पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए 5 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 वोटिंग काउंटिंग रूम बनाए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया- जिला परिषद सदस्यों के वोटो की काउंटिंग के लिए कुल 5 कमरे निर्धारित किए हैं। सभी 57 वार्डों की मतगणना के लिए कुल 98 टेबल निर्धारित की गई हैं। वार्ड संख्या 1 से 10 तक के 10 वार्डों की काउंटिंग होगी, जिसके लिए 18 टेबल लगाई जाएगी। इसी तरह वार्ड संख्या 15 से 26 तक के 12 वार्डों के लिए 19 टेबल, वार्ड संख्या 27 से 37 तक के 11 वार्डों के लिए 21 टेबल और वार्ड संख्या 38 से 50 तक के 13 वार्डों के लिए 20 टेबल निर्धारित की हैं। इसी तरह वार्ड संख्या 11 से 14 और51 से 57 तक के कुल 11 वार्डों की काउंटिंग के लिए 20 टेबल निर्धारित की गई हैं।

22 पंचायत समितियों के लिए 22 रूम तैयार

22 पंचायत समिति सदस्यों की काउंटिंग के लिए 22 रूम तैयार किए है। इसमें पंचायत समिति गोविंदगढ़ के लिए 7 टेबल, चौमूं के लिए 8 टेबल, किशनगढ़ रेनवाल के लिए 8 टेबल, जोबनेर के लिए 7 टेबल और झोटवाड़ा के लिए 5 टेबल निर्धारित की हैं। सांभरलेक के लिए 7 टेबल, दूदू के लिए 6 टेबल, मौजमाबाद के लिए 8 टेबल, आमेर के लिए 6 टेबल, जालसू के लिए 6 टेबल, रामपुरा डाबड़ी के लिए 6 टेबल, शाहपुरा के लिए 6 टेबल, अमरसर के लिए 6 टेबल, फागी के लिए 7 टेबल, माधोराजपुरा के लिए 7 टेबल, चाकसू के लिए 6 टेबल, कोटखावदा के लिए 6 टेबल,सांगानेर के लिए 6 टेबल, बस्सी के लिए 7 टेबल, तूंगा के लिए 6 टेबल, जमवारामगढ़ के लिए 8 टेबल और आंधी पंचायत समिति के लिए 6 टेबल निर्धारित की हैं।

राजस्थान के 6 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी:कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव घोषित, दानिश बरकरार, दिव्या को हटाया

द अनकवर्ड अपडेट





जयपुर। कांग्रेस हाईकमान ने राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों को गति देने के लिए गुरुवार देर रात बड़ा फेरबदल किया है। 81 नेताओं को एआईसीसी का सचिव नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया है। 25 निवर्तमान सचिवों और संयुक्त सचिवों को पदमुक्त कर दिया गया है।

फेरबदल में राजस्थान को खास तवज्जो मिली है। प्रदेश से जुड़े छह नेताओं को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय सचिव बनाया है। इनमें चार पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा जताया गया है, जबकि दो नए नेताओं को मौका मिला है। इनमें दानिश अबरार को न केवल रिपीट किया गया है, बल्कि दिल्ली की जिम्मेदारी भी दोबारा दी गई है। राजस्थान में संगठन का काम देख रहे तीन नेताओं को सचिव पद से हटा दिया गया है। इनमें दिव्या मदेरणा, संजना जाटव और विजय जांगिड़ शामिल हैं। राजस्थान की जिम्मेदारी देते हुए विश्वविजय सिंह, पोरलक खार्ते, डॉ. पलक वर्मा और मनोज बागड़ी को नया एआईसीसी सचिव बनाया है। इस तरह प्रदेश में संगठन की निगरानी और समन्वय के लिए 4 सचिवों की टीम काम करेगी।

सियासी मायने

राजस्थान पर संगठनात्मक फोकस : प्रदेश में चार सचिवों की नियुक्ति से कांग्रेस की संगठनात्मक निगरानी बढ़ेगी। आगामी चुनावों से पहले जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन को सक्रिय करना इनके सामने अहम चुनौती होगी।

संतुलन : राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के चार नेताओं को दोबारा जिम्मेदारी देकर अनुभव पर भरोसा जताया गया है। वहीं, दो नए चेहरों को मौका देकर नेतृत्व ने नए नेताओं को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। तीन नेताओं की छुट्टी से बदलाव का संदेश : दिव्या मदेरणा, संजना जाटव और विजय जांगिड़ को हटाया जाना प्रदेश की संगठनात्मक टीम में बदलाव का संकेत है। इससे नए सचिवों के लिए कामकाज और जवाबदेही की कसौटी भी तय होगी।

दूसरे राज्यों में राजस्थान के नेताओं की भूमिका : छह नेताओं को अलग-अलग राज्यों में जिम्मेदारी मिलने से राष्ट्रीय संगठन में राजस्थान की भागीदारी बढ़ेगी। इन नेताओं को दूसरे राज्यों में पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक कामकाज को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

4 पुराने चेहरों पर भरोसा, दो नए को मौका

राजस्थान से जुड़े छह नेताओं को दूसरे राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। दानिश अबरार को दिल्ली, धीरज गुर्जर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जगदीश चंद्र जांगिड़ को यूपी और रेहाना रियाज चिश्ती को महाराष्ट्र में सचिव बनाया गया है। हेम सिंह शेखावत को गुजरात और डूंगर राम गैदर को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेम सिंह शेखावत और डूंगर राम को पहली बार जिम्मेदारी दी गई है।

राजस्थान में संगठन सक्रिय करने की चुनौती

चार नए सचिवों की नियुक्ति को संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के सामने प्रदेश में गुटबाजी, नेताओं के बीच समन्वय और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की चुनौती है।

राजस्थान महिला मोर्चा की टीम यूपी में करेगी चुनाव प्रचार:पूर्व सांसद, विधायक, मेयर सहित 51 महिला नेता यूपी रवाना, अलग-अलग विधानसभाओं में संभालेंगी जिम्मेदारी

द अनकवर्ड अपडेट



जयपुर। अगले साल उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी ने प्रदेश महिला मोर्चा को विशेष जिम्मेदारी दी है। इसके तहत आज राजस्थान की 51 महिला नेता उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई।

इन महिला नेताओं में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, पूर्व सभापति, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा की विभिन्न इकाइयों से जुड़ी नेता शामिल हैं। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन महिला नेताओं के दल को उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किया।

इस मौके पर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष ने राखी राठौड़ ने कहा- यूपी में बीजेपी के शासन से पहले महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी के शासनकाल में यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है।

इसी संदेश को लेकर राजस्थान की महिला नेता यूपी में जाकर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार का जिम्मा संभालेंगी।

राजस्थान में गलनभरी सर्दी, तापमान 10 डिग्री से नीचे:शीतलहर की चपेट में कई इलाके, 2 दिन में और बढ़ेगी ठंड



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवा से राजस्थान में सर्दी तेज हो गई है। गुरुवार को सीकर, चूरू, पिलानी, फतेहपुर, अलवर, नागौर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।

अचानक तापमान गिरने से इन शहरों में रात में ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में सर्दी और बढ़ सकती है।

खासकर उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के एरिया में तापमान में? गिरावट होगी, जबकि दक्षिणी राजस्थान में अपेक्षाकृत थोड़ी कम सर्दी रहेगी।

पिछले 24 घंटे में सीकर के फतेहपुर में सबसे ज्यादा सर्दी रही। यहां रात का तापमान 6 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड हुआ।

मौसम के बड़े अपडेट्स

बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसमः राजस्थान में गुरुवार को सभी इलाकों में मौसम साफ रहा और दिनभर धूप रही। सर्द हवाओं के कारण गुरुवार दिन में तेज धूप में भी तापमान में गिरावट हुई। चूरू, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, फतेहपुर में सबसे सर्द रातः राजस्थान में गुरुवार को सबसे ज्यादा ठंडी रात फतेहपुर में रही, जहां न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहां सुबह-शाम गलनभरी सर्दी शुरू हो गई। फतेहपुर के अलावा सीकर में न्यूनतम तापमान 6.5, पिलानी में 9.7, चूरू, अलवर में 9.6, नागौर में 9.5 और करौली में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

दो दिन में सर्दी और बढ़ेगीः मौसम विशेषज्ञों ने बताया- राज्य में अगले एक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे शेखावाटी एरिया, बीकानेर संभाग के इलाकों में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है।

राजस्थान के प्रमुख शहरों का तापमान

जयपुर- गुरुवार सुबह-शाम तेज सर्दी रही, जबकि दिन में भी तेज धूप के बीच गर्मी का अहसास नहीं हुआ। जयपुर में गुरुवार दिनभर तेज धूप रहने के बावजूद उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच का आदेश,छोटी सजा मिलने पर कर्मचारी को प्रमोशन से इनकार नहीं कर सकते



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सरकारी सेवा में कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े मामले में कहा है कि सिविल सेवा नियम के तहत कर्मचारी की सात सालों में एक वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा पाने वाले कर्मचारी को प्रमोशन से मना नहीं किया जा सकता।

सीजे संजय के.अग्रवाल की अगुवाई वाली फुल बेंच ने यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि कार्यपालिका के परिपत्र केवल नियमों के खालीपन को भर सकते हैं, लेकिन वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी 2013 में निरीक्षक बने। 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को तीन लघु सजाएं दी गई। आरपीएस में पदोन्नति को लेकर विवाद खड़ा हुआ और खंडपीठ से होते हुए फुल बेंच के पास रेफरेंस के जरिए पहुंचा।

जयपुर शहर का 300वां गौरवशाली साल:यूरोपीय विद्वानों को नहीं मिले वेद तो 1789 में जयपुर के विद्वानों ने 1 साल में लिख कर दिए

द अनकवर्ड अपडेट

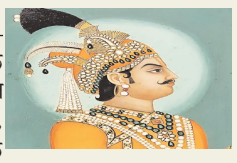

जयपुर। दुनिया को वेदों की प्रामाणिक पांडुलिपियां जयपुर ने ही करीब 237 साल पहले दी थीं। बंगाल, अवध, लखनऊ, आगरा, दिल्ली और बनारस में प्रयास करने के बावजूद चारों वेदों की प्रतियां नहीं मिलने पर यूरोपीय अधिकारी कर्नल एंटोनी लुई हेनरी पोलियर ने हवामहल के निर्माता और जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह (1778-1803) से संपर्क किया।महाराजा ने जयपुर के वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की हस्तलिखित प्रतियां तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। विद्वानों ने करीब एक साल में पांडुलिपियां तैयार कर सौंप दीं। मई 1789 में पोलियर ने वेदों की एक प्रति सर जोसेफ बैंक्स को ब्रिटिश म्यूजियम के लिए भेंट की, जबकि दूसरी प्रति सर विलियम जोन्स को सौंपी। ब्रिटिश म्यूजियम में चारों वेदों के संस्कृत पाठ की 11 वॉल्यूम आज भी सुरक्षित हैं।

ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी चारों वेदों के संस्कृत पाठ के 11 वॉल्यूम संरक्षित

संदेह दूर करने के लिए खोजे थे वेद यूरोप के विद्वानों में वेदों के वास्तविक स्वरूप व अस्तित्व पर संदेह था।

भाखड़ा नहर पर पुल ढहा, दो ट्रक फंसे, भीषण आग

पटियाला , एजेंसी। पंजाब के पटियाला में गुरुवार सुबह भाखड़ा नहर पर बना एक पुल ढह गया। हादसे में दो ट्रक पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए, जिसमें से एक में भीषण आग लग गई। हालांकि, गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना सुबह करीब छह बजे पटियाला-संगरूर बायपास (एनएच-07) पर हुई। करीब 60 मीटर लंबा स्टील ट्रस पुल अचानक ढह गया, जिससे बालू से भरा एक ट्रक और दूसरा ट्रक बीच में ही अटक गए। एक ट्रक चालक सुखविंदर सिंह ने बताया कि दूसरे ट्रक के फंसते ही उन्होंने अपना वाहन रोकने का प्रयास किया, जिससे उनके पैर में मामूली चोट आई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाया और पुलिस ने स्थिति संभाली। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रभावित मार्ग पर यातायात को तत्काल मोड़ दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बताया कि वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बाईं ओर के यातायात को सर्विस रोड पर मोड़ा गया है। घटनास्थल पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी, संकेतक और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। पुल ढहने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुसार, पुल पहले भी हिलता था और इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई थी। स्थानीय निवासी पवन कुमार ने पुल को करीब एक दशक पुराना बताया। एनएचएआई के अनुसार, चार लेन वाले पटियाला बायपास खंड को 2018 में उसे सौंपा गया था और अब यह मार्ग उसके अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध के तहत है। दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पंजाब लोक निर्माण विभाग की निगरानी में किया था। भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) के जिला अध्यक्ष अवतार सिंह भी घटना की सूचना मिलते ही मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

गोधरा कांड के सात दोषियों की पैरोल तीन सप्ताह बढ़ी

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों की पैरोल तीन सप्ताह बढ़ाने का आदेश दिया है। इन दोषियों को इसी वर्ष जून-जुलाई में चार महीने की पैरोल दी गई थी। अवधि बढ़ाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दोषियों ने अपनी सजा में छूट यानी रिमिशन के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन किया है, लेकिन उन पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि रिमिशन की अर्जियां अभी विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सजा माफी की अर्जियों पर निर्णय में देरी होना दोषियों की गलती नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने सातों दोषियों की पैरोल अवधि तीन सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया। मामले में आगे की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर लंबित रिमिशन अर्जियों के निर्णय पर निर्भर करेगी।

कोर्ट ने घर की कुर्की का दिया आदेश, नगीना सांसद को झटका

गाजियाबाद, एजेंसी। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा झटका लगा है। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई में पेश नहीं होने पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके घर की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। यह मामला साल 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा है, जिसकी शिकायत धर्मेंद्र कुमार ने की थी। इससे पहले, इसी अदालत ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। 17 नवंबर को उन्हें अदालत में मौजूद रहने को कहा गया था, ताकि उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। हालांकि, वह एक बार फिर गैरहाजिर रहे। बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की पूर्व निर्धारित बैठक में शामिल होने के कारण अदालत नहीं पहुंच सके। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र भी दिया था। लेकिन, अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। फिलहाल, अपने खिलाफ आए इस आदेश पर चंद्रशेखर आजाद की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

योगी का सपा पर वार: गुंडे-माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते



लखनऊ , एजेंसी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर रोड शो के दौरान हुई 14 वर्षीय मासूम आर्यवर्धन सिंह की मौत को लेकर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने सपा को माफिया पोषक करार देकर कहा कि गुंडे-माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते और उन्हें केवल डंडे से ही सीधा किया जा सकता है, जो काम उनकी सरकार कर रही है। सीएम योगी ने अपनी बात को बल देकर एक तीखी तुलना की। उन्होंने कहा, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह सपा के गुंडे-माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते। इन्हें डंडे से ही सीधा किया जा सकता है। उन्होंने सपा के रोड शो में व्याप्त अराजकता पर सवाल उठाकर कहा कि उनकी सरकार ने बेहतर सड़कें माफिया पोषक पार्टी के गुंडों को अराजकता फैलाने के लिए नहीं बनवाई हैं, बल्कि विकास और सुशासन के लिए बनाई हैं।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर हरी नाराजगी जाहिर की कि दुर्घटना के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे। उन्होंने भावुक होकर पूछा, आखिर उस होनहार मासूम आर्यवर्धन की गलती क्या थी? योगी ने घोषणा की कि वह स्वयं पीड़ित परिवार के घर जाएंगे और उन्हें हर हाल में न्याय दिलाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और माफियापोषक पार्टी के गुंडों को उनकी सही जगह दिखाई जाएगी।
अपने निर्धारित कार्यक्रमों के तहत, मुख्यमंत्री योगी ने इससे पहले वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जहां वनमंत्री अरुण कुमार ने विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की। इस कार्यक्रम के उपरांत, योगी आदित्यनाथ टाउनहॉल में जनचौपाल लगाएंगे और इसके बाद वे आर्यवर्धन के घर जाकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाएंगे।

झारखंड में इबोला को लेकर अलर्ट, अस्पतालों को 24 घंटे स्क्रीनिंग के निर्देश

रांची, एजेंसी। झारखंड में इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखकर राज्य की हेमंत सोरोन सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि, अब तक राज्य में इबोला संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और रिम्स, मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य संस्थानों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। मंत्री अंसारी ने अस्पतालों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। संदिग्ध मरीज मिलने पर तत्काल रिपोर्टिंग, जांच, आइसोलेशन और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट और जरूरी चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाने तथा राज्य के सभी 24 जिलों में 24 घंटे स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे पहले 12 नवंबर को रांची स्थित रिम्स में इबोला से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इबोला के लक्षण संक्रमण के 2 से 21 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। इनमें तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, उल्टी और दस्त शामिल हैं। गंभीर स्थिति में रक्तस्राव भी हो सकता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून और शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है, हवा से नहीं। मंत्री ने लोगों से घबराने और अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सतर्क रहने तथा लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील की।

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत बरकरार

● आजम ने कहा- देश आजाद है, लेकिन संविधान कैद

लखनऊ, एजेंसी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने से इंकार किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है और वह इसमें दखल नहीं देगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की सुनवाई इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना की जाए। आजम को



मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, इसके खिलाफ ईडी बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी ने गिरफ्तारी के आधार की जानकारी ने देने के आजम के दावे को गलत बताया। हालांकि, ईडी के जल्द सुनवाई के अनुरोध पर जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी की थी कि अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हैं, तब कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया था। इसके पहले आजम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हुए। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा पर रोक लगने के बाद उनकी रिहाई के दौरान हुई। रामपुर पहुंचने पर आजम ने अपनी रिहाई पर खुशी जताकर कहा कि उनका यह यकीन मजबूत हुआ है कि देश आजाद है, लेकिन संविधान कैद है। हम सभी को मिलकर संविधान की आजादी की मांग करनी चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करने वाला व्यक्ति ईडी का आरोपी हो सकता है और विश्वविद्यालय बना सकता है, तब उनकी अल्लाह से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो ताकि वह विश्वविद्यालय बना सके।

मोदी भी जेल में होते... लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ जांच बंद करवा दी

पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली का सनसनीखेज दावा



नई दिल्ली , एजेंसी । पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूपीए सरकार के दौरान हुई एक जांच को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर के ही कुछ नेताओं ने उस जांच को रुकवा दिया था, इसकी कीमत कांग्रेस आज चुका रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने 17 नवंबर को बेंगलुरु में यह बात कहकर राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने बताया कि जब वे कानून मंत्री थे (मई 2009-मई 2011), तब वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को गुजरात से बाहर किया गया था और वे जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। मोइली के अनुसार, इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आती और उन्हें भी राज्य से बाहर कर दिया जाता। लेकिन यह पार्टी के भीतर की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं, इसकारण पीएम मोदी के खिलाफ चल रही जांच को हमारी अपनी ही सरकार ने रुकवा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अन्य नेताओं के कारण हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली के दावे का संदर्भ शाह से जुड़े सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले से है। सीबीआई ने 2010 में अमित शाह को मामले में गिरफ्तार किया था, तब वे गुजरात के गृह राज्यमंत्री थे। सोहराबुद्दीन शेख एक गैंगस्टर था जिसकी 26 नवंबर 2005 को गुजरात के अहमदाबाद में एक एनकाउंटर में मौत हुई थी। हालांकि, मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 30 दिसंबर 2014 को शाह को मामले में आरोप-मुक्त कर दिया था।
मोइली ने फिलहाल इस मामले की विस्तृत जानकारी देने या उन कांग्रेस नेताओं के नाम उजागर करने से इंकार किया है, जिन पर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर और राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली के दावे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया देकर कहा है कि मोइली जैसे शक्तिशाली मंत्री रहे लोगों के पास इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य हो सकते है। उन्होंने गुजरात में एसआईटी के गठन और क्लीन चिट जैसे घटनाक्रमों का जिक्र कर कहा कि इतिहास निरंतर मूल्यांकन करता है और अपने को रिवाइज भी करता है। मोइली का यह बयान तब आया है जब कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटी है, और इस बयान ने कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।

संघ प्रमुख भागवत का दौरा मणिपुर में शांति बहाल करने में ठोस योगदान दे पाएगा

अब फिर आश्वासन देने की जरूरत नहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने उठाए सवाल

इम्फाल , एजेंसी। मणिपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता केशम मेघचंद्र सिंह ने सवाल उठाया है कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत का मौजूदा दौरा इस हिंसाग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में कोई ठोस योगदान दे पाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर को अब एक बार फिर आश्वासन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे ''स्थायी शांति, सुरक्षा, पुनर्वास, जवाबदेही और एक विश्वसनीय राजनीतिक रोडमैप की जरुरत है।'' भागवत तीन दिवसीय दौरे पर इंफाल पहुंच गए हैं। इस दौरान वह राज्य में संगठन की गतिविधियों और सामाजिक पहलों की समीक्षा करेंगे।
संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत राज्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का आकलन करेंगे। केशम ने पोस्ट में कहा कि मणिपुर को शांति चाहिए, केवल संगठनात्मक बैठकें नहीं। भागवत का 18 से 20 नवंबर तक मणिपुर दौरा हमारे राज्य में जारी संकट को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य लंबे समय से जातीय संघर्ष झेल रहा है। इस दौरान निर्दोष लोगों की जान गई, हजारों परिवार विस्थापित हुए, घर और आजीविका के साधन नष्ट हो गए और कई समुदायों के बीच खाई और गहरी हो गई है।
उन्होंने सवाल किया कि संघ प्रमुख भागवत का यह दौरा मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने में क्या ठोस योगदान देगा? क्या आरएसएस नेतृत्व हिंसा से प्रभावित विस्थापित परिवारों और समुदायों से सीधे बातचीत करेगा? सिंह ने यह भी पूछा कि क्या मेइती, कुकी-जो और नगा समुदायों के बीच विश्वास बहाली और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि क्या आरएसएस नेतृत्व लंबे समय से जारी इस संकट के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले राजनीतिक तंत्र की जिम्मेदारी पर भी बात करेगा?'' उन्होंने कहा कि संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और शताब्दी समारोह आरएसएस के आंतरिक एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन मणिपुर के लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंह ने कहा कि राज्य को अब और आश्वासनों की जरूरत नहीं है। उसे स्थायी शांति, सुरक्षा, पुनर्वास, जवाबदेही और एक विश्वसनीय राजनीतिक कार्ययोजना चाहिए।



उन्होंने कहा कि यदि आरएसएस नेतृत्व का बीजेपी के राजनीतिक नेतृत्व पर प्रभाव है, तो मणिपुर के लोगों को यह उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि उस प्रभाव का इस्तेमाल शांति, मेल-मिलाप और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाने में किया जाएगा। मई 2023 में घाटी में रहने वाले मेइती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं। इस संघर्ष के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस साल फरवरी से पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है।

चक्रवात अकवान का खतरा: ओडिशा में 80 हजार से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए



भुवनेश्वर , एजेंसी। ओडिशा सरकार ने चक्रवात 'अकवान' के आसन्न खतरे को देखकर अब तक 80 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ओडिशा राज्य में 74 बचाव दल तैनात किए गए हैं और एहतियात के तौर पर कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। जिला अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' शुक्रवार दोपहर तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के बीच, नरसापुर (आंध्र प्रदेश) और पुरी (ओडिशा) के पास गोपालपुर के पूर्व में दस्तक दे सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। गुरुवार सुबह यह आंध्र प्रदेश के नरसापुर से करीब 440 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 530 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था और बीते छह घंटों के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है।
ओडिशा के तटीय और दक्षिणी इलाकों में बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिसकी तीव्रता धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने कुल दो लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चक्रवात से गंजाम जिले के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है, जहां गुरुवार सुबह तक 36,398 लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया जा चुका था। जिले में 308 राहत केंद्र संचालित हैं, जहां विस्थापित लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, गंजाम में 1,098 गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीमें मलकानगिरि, कोरापुट, गंजाम, पुरी सहित विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं।
मौसम विभाग ने केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि समुद्र में उठने वाली लहरों के कारण गंजाम और पुरी के निचले इलाकों में 0.5 से एक मीटर तक पानी भर सकता है। चक्रवात के आगे बढ़ने के साथ दक्षिण और उत्तर ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिनकी रफ्तार फिलहाल 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे है और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है।

सोनिया गांधी नागरिकता मामला की सुनवाई 27 को

नई दिल्ली, एजेंसी । राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दायर निजी शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उस समय तक उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल नहीं की थी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है। इसी दिन पुलिस की ओर से दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। शिकायत सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उन्होंने सोनिया गांधी पर कथित तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है। अदालत अब पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही पर विचार करेगी।



सम्पादकीय

डबल इंजन की सरकार प्रदूषण से लाचार

बड़ा सवाल है पीएम मोदी की उस घोषणा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। क्या यह राष्ट्र नक्शे में ही बनेगा, क्या तब तक लोग स्वस्थ और जिंदा रह पांएगे। क्या साल 2047 तक ऐसे ही प्रदूषण की मार झेलनी पड़ेगी, जबकि इस वक्त दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। जब तक सडक़ों पर वाहनों की कुल संख्या घटाने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और पूरे एनसीआर में पूरे वर्ष कठोर कदम उठाने की रणनीति नहीं अपनाई जाएगी, तब तक दिल्ली को इस दमघोंटू स्थिति से मुक्ति मिलना कठिन है। लोकसभा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की तरफ से डबल इंजन की सरकार का नारा दिया गया था, ताकि विकास भी दुगनी रफ्तार से हो सके सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मोदी दिल्ली के प्रदूषण और सर्दियों के मौसम को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में नरेंद्र मोदी यह कहते हुए सुनाई देते हैं- 'इन्होंने दिल्ली का क्या हाल करके रख दिया है? जैसे ही सर्दियां आती हैं, इस प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों ने दिल्ली के हर मौसम को एक आपदा में बदल दिया है।' इसी तरह मोदी का एक वीडियो और भी है। यह 12 दिसंबर 2025 का संसदकालीन सत्र से पहले का है। मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित किया था। उन्होंने दिल्ली के भीषण प्रदूषण को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि, 'आप भी मौसम का मजा लीजिए', और फिर संसद को 'नाटक' करने की जगह नहीं बल्कि 'कार्य निष्पादन' की जगह बताते हुए अपना भाषण शुरू किया था। यह बात कहते हुए मोदी शायद यह भूल गए कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा गठबंधन की सरकार है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दिल्ली राज्य में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने सोशल मीडिया पर केंद्र और भाजपा शासित राज्यों को घेरते हुए सवाल उठाया कि 'हम वायु प्रदूषण में 'विश्व गुरु' क्यों बनते जा रहे हैं?' उन्होंने दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से पीएम 2.5 के आंकड़ों के गायब होने और पिछले साल के प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर भी सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए दावा किया कि भारत को विश्व गुरु बनाने के दावों के बीच देश प्रदूषण के मामले में भी शीर्ष पर पहुंच गया है और उन्होंने भारत में प्रदूषण से हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत का हवाला दिया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बार-बार 'बहुत खराब' से 'खतरनाक' श्रेणी में दर्ज किया गया है, कुछ क्षेत्रों में स्तर 440-500 से ऊपर दर्ज किए गए हैं। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर संस्था के ताजा आंकड़ों और रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बार-बार शीर्ष (नंबर-1) स्थान पर दर्ज किया गया है। नवंबर 2026 में दिवाली के आसपास दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक कुछ समय के लिए 581 से लेकर 1702 तक के खतरनाक स्तर को पार कर गया था, जो पाकिस्तान के लाहौर जैसे अन्य प्रदूषित शहरों से भी दोगुना से अधिक रहा। भारत में प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है।

किसानों को प्रत्यक्ष सबसिडी देने की दरकार

भारत में कृषि सबसिडी के कई प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार, इनपुट सबसिडी है। इनपुट सबसिडी में, उर्वरक सबसिडी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल कृषि सबसिडी 414614 करोड रुपए रही, जिसमें उर्वरक सबसिडी 186460 करोड रुपए रही। उर्वरक सबसिडी में अधिकांश न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी है और एक अन्य प्रकार यूरिया सबसिडी है। इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी के लिए 41533.81 करोड रुपए का प्रावधान केंद्रीय कैबिनेट ने किया, जो कि पिछले खरीफ मौसम (2025) में 37216.15 करोड रुपए से 4317.66 करोड़ रुपए अधिक था। रबी के मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी की घोषणा अभी बाकी है।

भारत में कृषि सबसिडी के कई प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार, इनपुट सबसिडी है। इनपुट सबसिडी में, उर्वरक सबसिडी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल कृषि सबसिडी 414614 करोड रुपए रही, जिसमें उर्वरक सबसिडी 186460 करोड रुपए रही। उर्वरक सबसिडी में अधिकांश न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी है और एक अन्य प्रकार यूरिया सबसिडी है। इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी के लिए 41533.81 करोड रुपए का प्रावधान केंद्रीय कैबिनेट ने किया, जो कि पिछले खरीफ मौसम (2025) में 37216.15 करोड रुपए से 4317.66 करोड़ रुपए अधिक था। रबी के मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी की घोषणा अभी बाकी है। वर्ष 2026-27 के लिए यूरिया सबसिडी के लिए 116799 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। पहले तो उर्वरक सबसिडी देने का तरीका भिन्न था, लेकिन वर्ष 2010 में इसे न्यूट्रिएंट आधारित कर दिया गया था, जिसके अनुसार चार पोषक तत्वों- नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, के आधार पर सबसिडी निर्धारित करना शुरू किया गया। ऐसा समझा गया कि न्यूट्रिएंट आधारित सबसिडी देने से उर्वरकों का संतुलित उपयोग होगा, मृदा यानी मिट्टी की सेहत बेहतर होगी और घरेलू उर्वरकों का उपयोग बढ़ेगा। लेकिन देखा गया कि उसके बावजूद कंपनियों के माध्यम से उर्वरक सबसिडी बदस्तूर जारी रही, आयातों पर निर्भरता बढ़ती रही और घरेलू उर्वरकों का उपयोग नहीं बढ़ पाया। लेकिन 2010 से पहले भी और 2010 में न्यूट्रिएंट आधारित सबसिडी देने के बाद भी सबसिडी सीधे किसानों को नहीं, बल्कि कंपनियों को दी जाती रही है। कंपनियों को सबसिडी उनके द्वारा बिक्री किए गए उर्वरकों के आधार पर दी जाती है। किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सबसिडी से लाभ किसानों को कम और कंपनियों को ज्यादा होता है। उर्वरक कंपनियां चाहे सहकारी क्षेत्र में हों, सरकारी हों अथवा निजी क्षेत्र में, सभी के लाभ ऊंचे बने हुए हैं और किसानों की मुश्किलें लगातार बरकरार हैं। उसको समय पर उर्वरक नहीं मिलते हैं और अन्यान्य कारणों से उसकी लागत तो लगातार बढ़ ही रही है, उसके लाभ कम होते जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कृषि लाभ का सौदा नहीं रही। लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि उर्वरक सबसिडी सीधे किसानों को मिलनी चाहिए, न कि कंपनियों के माध्यम से। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। पूर्व में सभी प्रकार की सबसिडी व्यावहारिक कारणों से अप्रत्यक्ष रूप से मिलती थी और बिचैलियों के कारण लाभार्थी को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन आज तकनीकी विकास से यह संभव हो सका है कि विभिन्न प्रकार की सबसिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच सके। जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल बैंकिंग यानी 'जैम त्रे' के कारण ऐसा संभव हो सका है। किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के खाते में पहुंच रही है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग हो रही है जिससे किसानों को उर्वरक सबसिडी भी सीधे तौर पर पहुंच सके। यदि ऐसा संभव हो सके तो किसानों को तो फायदा होगा ही, क्योंकि लगभग वो हिस्सा जो कंपनियों के खाते में जाता है, वो किसानों तक पहुंच सकेगा। इसके साथ कृषि को भी फायदा होगा और देश के धन का सही उपयोग हो सकेगा। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि किसानों को सबसिडी के कारण जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करना सस्ता पड़ता है, अब वह अपनी आवश्यकता के अनुसार गैर रासायनिक यानी जैविक उर्वरक अपना सकेंगे। यह सर्वथा सिद्ध है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले उत्पादों के बजाय उपभोक्ता स्वास्थ्य कारणों से जैविक खाद द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं को ही ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, भारत में बड़ी तादाद में पशु धन है और जैविक खाद के उत्पादन के लिए अभी तक अधिक प्रोत्साहन नहीं होने के कारण पशुधन का गोबर बेकार चला जाता है। लेकिन किसान को उर्वरक सबसिडी प्रत्यक्ष रूप से मिलने के कारण, वे जब जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करेंगे तो जैविक खाद के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन होगा और देश में गोबर का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसका तीसरा लाभ यह होगा कि जैविक खाद का उत्पादन ज्यादा होने के कारण किसान गोबर के लिए ज्यादा पशु रखना चाहेंगे। इससे देश में डेयरी उत्पादन भी बढ़ सकेगा, जिससे किसान की आमदनी और बढ़ सकेगी। चौथे, रासायनिक उर्वरकों पर सबसिडी के चलते इन उर्वरकों का वैज्ञानिक और आर्थिक आधार पर इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता और देश के संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यदि किसान के खाते में सबसिडी पहुंचे तो वह अधिक वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करेगा। पांचवां, सबसिडी के बल पर कृषि भूमि पर ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अन्य पोषक तत्व (न्यूट्रिएंट्स), जो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, की लगातार कमी हो रही है।



सामाजिक सद्भाव की ताकत बताता ये दिन

देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती है। 19 नवंबर, 1917 को जन्मीं इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की प्रभावशाली और ऐतिहासिक हस्तियों में शामिल रही हैं। उनके जन्मदिन पर 'कौमी एकता दिवस' का आयोजन हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व पर विचार करने का अवसर देता है। इस अवसर पर 19 से 25 नवंबर तक 'कौमी एकता सप्ताह' भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकीकरण और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है।सच यही है कि भारत की पहचान उसकी भौगोलिक सीमाओं से ही नहीं, बल्कि उसकी बहुधार्मिक, बहुभाषायी और बहुसांस्कृतिक विरासत से भी है। यहां अलग-अलग धर्मों के लोग अपनी-अपनी आस्था के साथ रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न परंपराएं जीवन को विविध रंगों से भरती हैं। इतनी विविधताओं के बावजूद भारत का एक राष्ट्र के रूप में कायम रहना उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन यह एकता अपने आप बनी रहने वाली व्यवस्था नहीं है। इसे आपसी विश्वास, सहिष्णुता, समानता और भाईचारे के निरंतर प्रयासों से मजबूत करना पड़ता है। किसी देश की एकता केवल राष्ट्रीय पर्वों पर नारे लगाने से मजबूत नहीं होती, बल्कि तब मजबूत होती है, जब नागरिक एक-दूसरे की धार्मिक आस्थाओं, भाषाओं, खान-पान और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय एकता तभी मजबूत होगी, जब किसी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के कारण भेदभाव का सामना न करना पड़े। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, कमजोर वर्गों को समान अवसर, महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक न्याय की स्थापना भी इसी दिशा के महत्वपूर्ण कदम हैं। विकास का लाभ जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी राष्ट्रीय एकता की भावना वास्तविक अर्थों में मजबूत होगी। भारत की असल शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता है। इस विरासत को बचाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। 19 नवंबर का संदेश यही होना चाहिए कि हमारी धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक पहचान अलग-अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान एक है। जब हम संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर भारतीयता को प्राथमिकता देंगे, तभी देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। अंततः यही भावना भारत को एक शांतिपूर्ण, समावेशी, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।



2027 में शनि की क्रूरता में आएगी कमी, 4 महीने वृषभ समेत 6 राशियों को सबसे अधिक लाभ

शनि 2027 में सबसे पहले बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र में आने से शनि की क्रूरता में कमी आएगी और 6 राशियों के लिए कल्याणकारी साबित होंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय देवता और कर्म फलदाता माना जाता है। शनि की चाल में होने वाला बदलाव मेष से लेकर मीन राशि के आर्थिक, करियर, व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालता है। 2027 में शनि की चाल में कई बार बदलाव देखने को मिलेंगे। पंचांग के अनुसार, शनि 2027 में सबसे पहले बुध के प्रभाव में आएंगे। 8 फरवरी 2027 को शनि का रेवती नक्षत्र परिवर्तन होगा और इस नक्षत्र में करीब 4 महीने 03 जून 2027 तक रहेंगे। मित्र ग्रह बुध के प्रभाव में आने से शनि की क्रूरता में कमी आएगी और शनि के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। इस दौरान 6 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में अचानक और सबसे अधिक अच्छे बदलाव और लाभ होंगे। जानें शनि का रेवती नक्षत्र परिवर्तन किस राशि के लिए रहेगा अच्छा।

रेवती नक्षत्र में शनि का फल-रेवती नक्षत्र 27वां और अंतिम नक्षत्र है। अंतिम नक्षत्र होने के कारण यह समापन और नई शुरुआत से जुड़ा है। इस दौरान लोगों को अधूरे कामों को पूरा करने और नए दौर की शुरुआत के लिए अवसर मिलते हैं। शनि की कठोरता और अनुशासन संतुलित होते हैं। इस दौरान जातक थोड़े अधिक जिम्मेदारी और ऊर्जावान होते हैं।

रेवती नक्षत्र में शनि गोचर से किन राशियों को लाभ

वृषभ राशि-वृषभ राशि वालों को शनि नक्षत्र परिवर्तन से पदोन्नति या प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपकी ऊर्जा और उत्साह में कई गुना वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिनका आप लाभ उठाएंगे। नौकरी की तलाश अब खत्म हो सकती है।

मिथुन राशि-मिथुन राशि वालों को इस समय कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे। अटके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे।

कन्या राशि-कन्या राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक तौर पर बड़ा बदलाव लाएगा।





जमीन पर गलती से भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, लगता है वास्तु दोष

वास्तु के नियम के अनुसार कुछ चीजें जमीन पर रखने से वास्तु दोष लगता है। जानें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें गलती से भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए?

किन चीजों को जमीन पर रखने से लगेगा वास्तु दोष?वास्तु नियम के अनुसार हमें जमीन पर कुछ चीजों को ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। जाने-अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं लेकिन इससे घर में वास्तु दोष लग जाता है। दोष लगने से जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें और बाधाएं आने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन चीजों को सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए?

पूजा-पाठ का सामान- वास्तु मान्यता के अनुसार पूजा-पाठ से जुड़ी किसी भीचीज को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। भगवान की मूर्ति से लेकर घंटी, शंख, प्रसाद की कटोरी और थाली वगैरह को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को हमेशा आसन या फिर ऊंची जगह पर ही रखना चाहिए।

दीया-वास्तु के अनुसार दीए को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप रोजाना तुलसी के पास और घर के मुख्यद्वार के पास दीया जलाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। दिए नीचे आप फूल की पंखुड़ियां रख सकते हैं। इसके अलावा प्लेट या फिर चावल रखे जा सकते हैं।

तुलसी का पौधा-वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है। इसे घर में रखने से बरकत आती है। हालांकि इसके गमले को सीधे जमीन पर रखने से बचना चाहिए। इसे किसी ऊंची जगह या फिर स्टैंड पर रखना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी का पौधा अगर अच्छी तरह से बढ़ेगा तो इससे घर में खुशहाली आएगी।

जमीन पर ना रखें पैसे-वास्तु नियम के हिसाब से पैसों को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। ऐसे में पैसों को जमीन पर रखना मां लक्ष्मी के अनादर करने जैसा है। पैसों को हमेशा अलमारी, लॉकर या फिर किसी ऊंची जगह पर ही रखना सही नियम है।

घर की एनर्जी ऐसे रहेगी क्लीन-वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से घर में हर एक चीज को सही जगह ही रखना चाहिए। पूजा-पाठ से जुड़े सामान को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसे समय पर पानी दें और देखभाल करें। वहीं पैसों को हमेशा सिक्योर जगह ही प्लेस करें। हर एक चीच का प्लेसमेंट सही जगह होने से घर की एनर्जी क्लीन और पॉजिटिव रहती है।



'आई प्ले रॉकी' के प्रीमियर पर कार्तिक आर्यन ने दिया सपनों, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास रखने के महत्व का संदेश

मुंबई फिल्म 'आई प्ले रॉकी' के प्रीमियर पर कार्तिक आर्यन ने सपनों, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास रखने के महत्व को लेकर एक दिल छू लेने वाला संदेश दिया। फिल्म को सपने देखने वालों और अपने सपनों पर विश्वास करने वालों की कहानी बताते हुए अभिनेता ने कहा कि यह उन सभी लोगों से जुड़ाव महसूस कराएगी, जिन्हें कभी न कभी यह कहा गया है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं।

अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, 'यह फिल्म उन सभी लोगों के बारे में है, जो सपने देखते हैं और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग, जिनसे अक्सर कहा जाता है कि 'नहीं हो सकता, यह तू कभी नहीं बन सकता, यह कभी नहीं बन सकती।' मेरा मानना है कि यह फिल्म आपको विश्वास दिलाएगी कि आप यह कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।'

अपने सफर से फिल्म की तुलना करते हुए कार्तिक ने बताया कि किस तरह ओरिजिनल फिल्म 'रॉकी' कई पीढ़ियों को प्रेरित करती आई है। उन्होंने यह भी साझा किया कि फिल्म का मशहूर गाना 'आई ऑफ द टाइगर' मुश्किल वक्त में उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, 'मेरे सफर में कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं खुद को निराश महसूस करता हूं, तो 'आई ऑफ द टाइगर' एक ऐसा गाना है, जो मेरे लिए थीम सॉन्ग की तरह है और मुझे बहुत प्रेरित करता है। इसके बाद मैं बाकी चीजों से ध्यान हटाकर दोबारा अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू कर देता हूं।'

कार्तिक की ये बातें उस समय और भी खास हो गईं, जब उन्होंने ऐसे संदेश पर बात की, जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके अपने सफर से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। चुनौतियों का सामना करने से लेकर अपनी अलग पहचान बनाने तक, कार्तिक की कहानी फिल्म के बड़े संदेश यानी दृढ़ता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। प्रीमियर पर उनकी स्पीच ने इस बात को रेखांकित किया कि आलोचनाओं, असफलताओं और दूसरों की सोच की परवाह किए बिना अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित रखना कितना जरूरी है।

फिल्म को लेकर अपना उत्साह जाहिर करते हुए कार्तिक ने सिनेमा और 'आई प्ले रॉकी' के नाम एक जाम उठाया। साथ ही उन्होंने दर्शकों से फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन मिस न करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वह खुद फिल्म देख चुके हैं और इसे दोबारा देखने की योजना बना रहे हैं। उनके मुताबिक, फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन दर्शकों के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है। प्रीमियर पर अपनी बातों के जरिए कार्तिक ने दर्शकों को एक खास संदेश दिया कि अपने सपनों पर विश्वास रखें, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें और किसी को भी यह न कहने दें कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते।

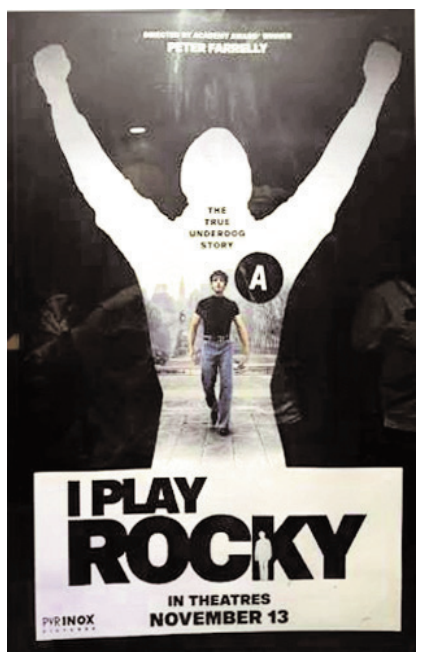

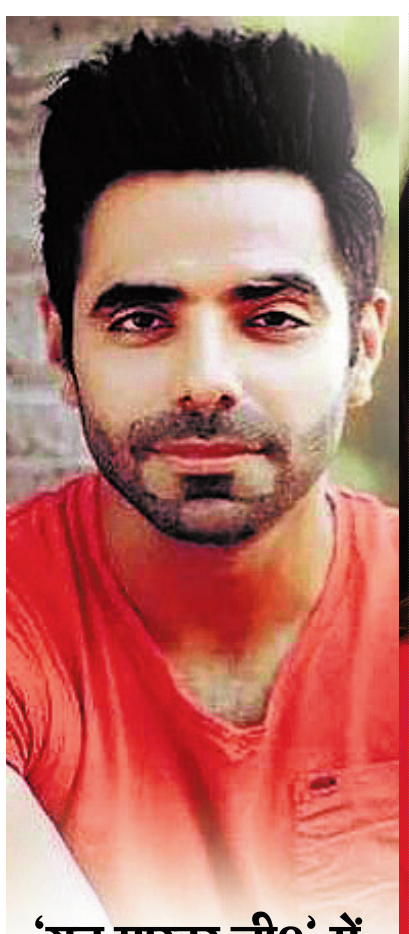

'गन मास्टर जी9' में दिखेगा अपारशक्ति का खतरनाक अवतार

जब भी अपारशक्ति खुराना का नाम आता है, तो सबसे पहले स्त्री के प्यारे और मजेदार दोस्त बिट्टू की याद आती है, जो 'सॉफ्ट चिट्ठी, वॉर्म चिट्ठी' कहते नजर आते हैं। लेकिन अब अपारशक्ति ने अपने इस पुराने अंदाज को पीछे छोड़ दिया है। 'गन मास्टर जी9' में वह एक ऐसे खतरनाक विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं!

फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसमें अपारशक्ति का ऐसा रूप देखने को मिला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना तो तय है कि फिलहाल बिट्टू की मासूमियत को भूल जाइए, क्योंकि अब पर्दे पर उनका खतरनाक अंदाज छाने वाला है।

फिल्म में अपारशक्ति की पहली झलक से ही साफ हो जाता है कि वह इस बार एक अलग ही रूप में नजर आने वाले हैं। उनकी डरावनी नजरें, चेहरे के भाव और डायलॉग बोलने का अंदाज उनके किरदार को और भी खतरनाक बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्शन के मामले में भी वह किसी से पीछे नहीं हैं। उनके लड़ाई वाले दृश्य और जबरदस्त अंदाज उनके किरदार में एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। फिल्म में अपारशक्ति, इमरान हाशमी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आते हैं। ऐसे में दोनों के बीच होने वाली टक्कर को पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अपारशक्ति का लुक भी उनके इस नए किरदार को खास बनाता है। कंधों तक लंबे और बिखरे हुए बाल, रंग-बिरंगी प्रिंट वाली शर्ट, धातु के फ्रेम वाला चश्मा और बोलने का अलग अंदाज उनके किरदार को एकदम देसी और खुरदरा रूप देते हैं। खास बात यह है कि अपारशक्ति अपने किरदार को दमदार बनाने के लिए न तो किसी बड़े फिल्मी अंदाज में एंट्री लेते हैं और न ही ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। उनका अंदाज और उनका बेखौफ व्यक्तित्व ही उनकी मौजूदगी का एहसास करा देता है। ट्रेलर देखकर तो यही लगता है कि बॉलीवुड में अब विलेन के किरदारों को एक नए अंदाज में पेश किया जा रहा है और अपारशक्ति इस बदलाव की एक शानदार मिसाल बनने वाले हैं! 'गन मास्टर जी9 आगामी 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



साउथ एक्टर्स को हिंदी एक्सेंट के लिए ट्रोल करना 'बिल्कुल सही नहीं' है

'जेलर 2' की एक्ट्रेस अपेक्षा पोरवाल ने कहा कि साउथ इंडियन एक्टर्स को उनके हिंदी एक्सेंट के लिए ट्रोल किया जाना 'बिल्कुल सही नहीं' है। खास बातचीत में अपेक्षा ने बताया कि मजाक उड़ाने के बजाय एक्टर की मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग एक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए तो शायद वे खुद भी कोई दूसरी भाषा नहीं बोल पाएंगे।

अपेक्षा से पूछा गया, 'आजकल, साउथ इंडियन एक्टर्स को अक्सर सोशल मीडिया पर उनके हिंदी एक्सेंट और बोलने के तरीके के लिए ट्रोल किया जाता है। आप इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं? क्या उन आर्टिस्ट्स का मजाक उड़ाना सही है, जो दूसरी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे हैं?'

यह समझाते हुए कि जिस भाषा को आप अच्छी तरह नहीं जानते, उसमें काम करना कितना मुश्किल है, उन्होंने आईएएनएस को बताया, 'हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई किसी खास भाषा में कम्फर्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे सीखने और बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमें उस कोशिश की तारीफ करनी चाहिए, न कि उस पर हंसना या उसे ट्रोल करना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि अगर इन्हीं ट्रोल्स से दूसरी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो शायद वे खुद ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब कोई कड़ी मेहनत कर रहा हो और कोशिश कर रहा हो, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, बुराई नहीं।'

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को हाल ही में अपने हिंदी एक्सेंट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। चैट शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 में आने के दौरान 'एनिमल' फेम एक्ट्रेस ने बताया कि अपने पूरे करियर में उन्हें अपने एक्सेंट को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालांकि, रश्मिका ने कहा कि उन्होंने कभी भी आलोचना को अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री और भाषाओं में काम करने से रोकने नहीं दिया। रश्मिका ने बताया कि साउथ इंडिया से होने की वजह से उनका एक्सेंट नेचुरली आता है। एक्ट्रेस ने आगे जोर देकर कहा कि वह खुद को एक इंडस्ट्री तक लिमिट करने के बजाय कई भाषाओं में काम करना चाहती हैं।



ग्लोबल म्यूजिक स्टेज पर दोसांझ, दुआ लीपा और मैडोना संग परफॉर्म करेंगे दिलजीत दोसांझ

पंजाबी म्यूजिक का जलवा अब दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अपने म्यूजिक से इंटरनेशनल स्टेज पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में शामिल कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल 2027 में परफॉर्म करते नजर आएंगे। फेस्टिवल के आयोजकों ने अगले साल होने वाले इस इवेंट की कलाकारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दिलजीत के साथ दुआ लीपा, टेम इम्पाला और एसजेडए जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा पॉप म्यूजिक की दिग्गज सिंगर मैडोना, जेआईएसओओ, फोएबे ब्रिजर्स और रोबिन भी इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। कोचेला 2027 का आयोजन कैलिफोर्निया के इंडियो स्थित एम्पायर पोलो क्लब में होगा। यह फेस्टिवल दो वीकेंड में आयोजित किया जाएगा। पहला वीकेंड 9 से 11 अप्रैल और दूसरा वीकेंड 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। इस बार शुक्रवार को दुआ लीपा, शनिवार को टेम इम्पाला और रविवार को एसजेडए हेडलाइनर के तौर पर परफॉर्म करेंगे। तीनों कलाकार अपने अलग-अलग म्यूजिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जहां दुआ लीपा अपने पॉप म्यूजिक से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी, वहीं टेम इम्पाला साइकेडेलिक रॉक और एसजेडए आरएंडबी म्यूजिक का रंग जमाएंगी।

2023 में भी कोचेला का हिस्सा बने थे दिलजीत

भारतीय फैंस के लिए इस बार दिलजीत दोसांझ का नाम लिस्ट में शामिल होना खास है। दिलजीत इससे पहले साल 2023 में भी कोचेला फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं। उस समय उन्होंने पंजाबी भाषा में गाने गाकर दुनियाभर के दर्शकों का ध्यान खींचा था। वह इस फेस्टिवल के मंच पर परफॉर्म करने वाले शुरुआती पंजाबी भाषा के कलाकारों में शामिल थे। अब 2027 में उनकी वापसी से एक बार फिर पंजाबी म्यूजिक को इंटरनेशनल पहचान मिलने की उम्मीद है।

मैडोना समेत ये बड़े कलाकार भी आएंगे नजर

इस बार कोचेला की लिस्ट में पॉप म्यूजिक की दिग्गज सिंगर मैडोना का नाम भी शामिल है। वह शुक्रवार को डांस टेंट में परफॉर्म करेंगी। वहीं डेडी यांकी को 'इन द डेजर्ट' स्पेशल बिलिंग दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की मशहूर जोड़ी जस्टिस भी अपने गाने 'ब्लाइंडेड बाय द लाइट्स' के साथ बंकर में डेब्यू करेगी। फेस्टिवल के पहले दिन यानी शुक्रवार को जारा लार्सन, स्टीव लैसी, जेआईएसओओ, पैगी गू, केलेनी, लियोन थॉमस और जॉर्जियो मोरोडर जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। वहीं शनिवार को फोएबे ब्रिज, वीजर, रोबिन, मैनेस्किन, एनसीटी, लियोन ब्रिजेस, टिएस्टो, मार्टिन गैरिक और अंडरवर्ल्ड जैसे नाम शामिल हैं। रविवार को डॉन टॉलिवर, डोम डॉला, कायगो, एम्पायर ऑफ द सन, फोर टेट, द नेबरहुड, बेकी जी, बेबीमॉन्स्टर, विक्टोरिया मोनेट और जोरजा स्मिथ अपनी परफॉर्मेंस देंगे।

नील आपको यह एहसास नहीं होने देते कि आप किसी सीनियर अभिनेता के साथ काम कर रहे हैं



अभिनेत्री कशिका कपूर सॉन्ग 'बेवफा से' में नील नितिन मुकेश के साथ नजर आ रही हैं। उनके साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए कशिका ने बताया कि वह कभी आपको यह एहसास नहीं होने देते कि आप किसी सीनियर अभिनेता के साथ काम कर रहे हैं। अभिनेत्री कशिका कपूर ने बातचीत में अभिनेता नील नितिन मुकेश के साथ काम करने के अनुभव को मजेदार बताते हुए कहा, 'किसी सीनियर एक्टर से आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और नील को इंडस्ट्री में कई साल काम करने का काफी अनुभव है। यह एक शानदार सीखने वाला अनुभव था और हमने खूब मस्ती भी की। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही हूं।' अभिनेत्री ने बताया कि शूट होने से पहले उन्हें गाने के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई गई थीं। उन्होंने कहा, 'नील नितिन मुकेश के आने से कुछ महीने पहले ही यह प्रोजेक्ट लॉक हो गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह गाना सच में बनेगा या इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। आखिर में जब नील नितिन मुकेश फाइनल हुए तो मेकर्स ने गाने की धुन को देखते हुए इसमें एक डांस नंबर जोड़ने का फैसला किया। हमने रिहर्सल शुरू की और सब कुछ काफी अच्छा हुआ। तभी कहानी भी तैयार हुई।'

कशिका कपूर ने बताया, 'मुझे उम्मीद थी कि गाना लोगों को पसंद आएगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कमाल का है। मुझे लगता है जेन जी इस कहानी से इसलिए जुड़ रहे है, क्योंकि हमारी जनरेशन में ऐसी चीजें काफी आम होती जा रही हैं। ओपन रिलेशनशिप और धोखा जैसी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं और शायद यही वजह है कि दर्शक इस गाने से इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'लोगों ने हमारे गाने को खुले दिल से अपनाया है और इतना प्यार दिया है। मैं इस रिस्पॉन्स के लिए बहुत आभारी हूं। लोग मेरे डांस और एक्सप्रेशन्स की तारीफ कर रहे हैं और मुझे लगता है सबको यह गाना पसंद आ रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है।



भारत में टेनिस का रोमांच बढ़ाएगी वर्ल्ड लीग, 5वें सीजन में कई दिग्गज खिलाड़ी दिखाएंगे दम

एजेंसी, बेंगलुरु

वर्ल्ड टेनिस लीग (डब्ल्यूटीएल) अपने पांचवें सीजन के लिए अंतरराष्ट्रीय टेनिस के कुछ सबसे बड़े नामों को बेंगलुरु लाने के लिए तैयार है। 16 खिलाड़ियों की सूची में पूर्व विश्व नंबर-3 एलिना स्वितोलिना, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बेलिंडा बेनसिक, पूर्व विश्व नंबर-1 करोलिना प्लिस्कोवा, विंबलडन फाइनलिस्ट निक किर्गियोस और दो बार के विंबलडन डबल्स चैंपियन हैरी हेलियोवारा मुख्य आकर्षण होंगे। आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स द्वारा लाइसेंस प्राप्त और प्रबंधित यह लीग 17 से 20 दिसंबर तक बेंगलुरु के एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। सीजन 5 में चार टीमें एक्विक्स ईगल्स, गेम चेंजर्स फाल्कन्स, ऑसी मावेरिक्स काइट्स और वीबी रियल्टी हॉक्स हिस्सा लेंगी। इनमें आठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और भारत के आठ प्रमुख टेनिस खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे। महिला वर्ग की अगुवाई यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना करेंगी, जो 20 बार की डब्ल्यूटीए



सिंगल्स चैंपियन और 2018 डब्ल्यूटीए फाइनल्स की विजेता हैं और इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। उनके साथ स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिक भी मुख्य आकर्षण होंगी, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता था और 2025 में विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट रही थीं।

इस सूची में चेक गणराज्य की करोलिना प्लिस्कोवा भी शामिल हैं, जो पूर्व विश्व नंबर-1 और दो बार की ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट हैं। स्पेन की पाउला बडोसा, जो पूर्व विश्व नंबर-2 और 2021 इंडियन वेल्स चैंपियन हैं, पिछले सीजन के बाद एक बार फिर इस लीग में वापसी कर रही हैं। पुरुष वर्ग का लाइन-अप भी उतना ही दमदार है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस बेंगलुरु के कोर्ट पर अपना जलवा बिखेरेंगे। 2022 के विंबलडन फाइनलिस्ट और उसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स चैंपियन रहे किर्गियोस के साथ कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक भी जुड़ेंगे, जो नौ बार के एटीपी खिताब विजेता हैं और जनवरी, 2026 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग नंबर-10 पर पहुंचे थे। बेल्जियम के जिजौ बर्ग्स, जिन्होंने इस साल ईस्टबोर्न में अपना पहला एटीपी खिताब जीता और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा, जो दो बार के विंबलडन पुरुष डबल्स चैंपियन (2024 और 2026) हैं, अंतरराष्ट्रीय लाइन-अप को पूरा करते हैं। भारत के प्रतिनिधित्व में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा प्रतिभाओं का मजबूत मिश्रण देखने को मिलेगा। क्ले कोर्ट पर एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी सुमित नागल, भारत के प्रमुख डबल्स खिलाड़ी युकी भांबरी के साथ वापसी कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर सुरेश भी टीम का हिस्सा होंगे।

पूर्व एटीपी सिंगल्स फाइनलिस्ट और दो बार के एटीपी 250 डबल्स चैंपियन रामकुमार रामनाथन भी शामिल हैं। भारतीय महिला लाइन-अप में 17 वर्षीय माया राजेश्वरन रेवती और श्रीवल्ली रश्मिका भामिदिपति की वापसी होगी, जो पिछले सीजन में भी खेली थीं। उनके साथ रुतुजा भोसले (जिन्होंने 2023 एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता था) और वैष्णवी अडकर (2026 में भारत की नंबर-1 महिला सिंगल्स खिलाड़ी) भी जुड़ेंगी।

'हम अपना खेल खेलना चाहते हैं', एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सलीमा टेटे ने बताई टीम की रणनीति

एजेंसी, भोपाल



मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की शुरुआत से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने साफ कर दिया है कि टीम का पूरा ध्यान विरोधियों की रणनीति पर नहीं बल्कि अपने खेल और प्रदर्शन पर रहेगा। सलीमा के मुताबिक, टीम कोच के निर्देशों और अपने गेम प्लान के अनुसार मैदान पर उतरेगी। 19 से 28 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में मैजूदा चैंपियन भारत का सामना चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड से होगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। राउंड-रॉबिन चरण के अंत में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 19 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेंगे। इसके बाद 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड और 24 नवंबर को चीन से और 25 नवंबर को जापान के खिलाफ मैच होगा। सेमीफाइनल 27 नवंबर को और मेडल मैच 28 नवंबर को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले हॉकी इंडिया की ओर से जारी बयान में भारतीय कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं। हम बस खुद पर, टीम की संरचना पर और कोच के निर्देशों का पालन करने पर ध्यान दे रहे हैं। संक्षेप में कहें तो, हम अपना खेल खेलना चाहते हैं। मुख्य कोच सजोर्ड मारिन ने कहा कि हम चाहते हैं कि खिलाड़ी अलग-अलग पोजिशन पर खेल सकें। इससे टीम की गहराई बढ़ती है और अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो यह बहुत मददगार साबित होता है, खासकर ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में। साथ ही, यह खिलाड़ियों के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि क्या इससे हमारे खेलने के तरीके में कुछ नया जुड़ता है और क्या इससे टीम में वे सुधार आते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मेजबान टीम भारत शानदार फॉर्म में है लेकिन चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीमों के खिलाफ मजबूती से खेलना होगा। भारतीय टीम ने तीन बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। मेजबान टीम के पास दक्षिण कोरिया से आगे निकलने का मौका है, जिसके नाम भी तीन खिताब हैं।

हमारा लक्ष्य खेल विश्वविद्यालयों को संपूर्ण खेल पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बनाना है : मांडविया

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि हमारा लक्ष्य खेल विश्वविद्यालयों को संपूर्ण खेल पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बनाना है, जहां खिलाड़ी, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रतियोगिताएं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा सभी एक साथ विकसित किए जा सकें। मांडविया ने आज यहां देश के 13 खेल विश्वविद्यालयों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खेल विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को मजबूत करने, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने तथा भारत की खेल शिक्षा,



अनुसंधान, प्रशिक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने जैसे विषयों पर केन्द्रित चर्चा की गई। केंद्रीय खेल मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों को देश के हित के लिए विशिष्ट खेलों में अपनी विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता विकसित करने की आवश्यकता है। चाहे वह किसी विशेष खेल, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान या अनुसंधान में हो। इससे पूरे देश को लाभ होगा। विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों का विकास करें। उन्होंने उन्हें विश्वविद्यालयों को एक-दूसरे के साथ ज्ञान साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मांडविया ने कहा कि हम अब अलग-थलग रहकर काम नहीं करेंगे। अपने प्रयासों, संसाधनों और विशेषज्ञता को एकीकृत करके, हम एक मजबूत, सहयोगात्मक राष्ट्रीय खेल प्रणाली का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के बीच प्रशिक्षकों और ज्ञान के आदान-प्रदान और संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल मंत्री ने विश्वविद्यालयों को ऐसी प्रणालियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जो भारत को अपने खेल पारिस्थितिकी तंत्र और उद्योग को समग्र रूप से विकसित करने में सहायता करेंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को खेल विज्ञान, खेल कानून और खेल पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि पूरे भारत में इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों और मजबूत संस्थागत क्षमताओं का विकास हो सके।

घुटने की सर्जरी के चलते दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर हुए जैकब बेथेल, आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे

एजेंसी, नई दिल्ली

इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल घुटने की चोट के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। उन्हें अपने दाएं घुटने की सर्जरी करानी होगी। इस वजह से वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी व्हाइट बॉल सीरीज के साथ-साथ दिसंबर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन में भी नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी वेबसाइट के मुताबिक बेथेल 2026 में ज्यादातर समय घुटने की समस्या से जूझते रहे हैं। उन्होंने जुलाई में भारत के खिलाफ



लॉर्ड्स में वनडे मुकाबले में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। इस मैच में उन्होंने 91 रन की पारी खेली थी। इसके बाद से वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेले हैं। 23 वर्षीय बेथेल को ऑस्ट्रेलिया में जारी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम से जुड़ना था। इसके बाद उन्हें दिसंबर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी जाना था। हालांकि, घुटने की चोट दोबारा उभरने के कारण उन्हें दोनों सीरीज से बाहर होना पड़ा है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जैकब बेथेल के दाहिने घुटने की इस हफ्ते सर्जरी होगी और उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर कर दिया गया है। अब यह देखना होगा कि बेथेल फरवरी में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज और मार्च में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले एकमात्र डे-नाइट टेस्ट तक फिट हो पाते हैं या नहीं। इंग्लैंड को इसके बाद 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज और आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है। ऐसे में बेथेल की फिटनेस टीम के लिए अहम होगी। घुटने की चोट के कारण बेथेल आईपीएल 2027 में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने उन्हें टीम से रिलीज किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि जैकब बेथेल को रिलीज करना हमारे लिए बेहद मुश्किल फैसला था।

बिजनेस

गोयल ने रोम में प्रमुख इतालवी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकें कीं, अहम मुद्दों पर चर्चा

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रोम में प्रमुख इतालवी कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठकें कीं। इस बैठक में ऊर्जा उपकरण, निर्माण, विमानन, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा संयुक्त उद्यमों पर चर्चा हुई।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि गोयल ने इटली के रोम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान 17 नवंबर को इटली की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने वाल्टर टोस्टो एस.पी.ए. के प्रबंध निदेशक लुका टोस्टो, नॉर्डइम्पियांटी सिस्टम एस.आर.एल. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जियान पिएरो गाग्लियार्डी, एटिटेक के अध्यक्ष जियानी लेटिएरी, मागाल्डी ग्रीन एनर्जी की प्रबंध निदेशक सुश्री लेटिजिया मागाल्डी और ब्राको इमेजिंग एस.पी.ए. के



मुख्य कार्यकारी अधिकारी फुल्वियो रेनोल्डी ब्राको के साथ बैठकें कीं।

गोयल के साथ इन बैठकों में भारत में इटली का निवेश बढ़ाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इतालवी कंपनियों ने अपनी प्रौद्योगिकियां भारत लाने और विनिर्माण, विमान रखरखाव, थर्मल ऊर्जा भंडारण तथा औषधीय सामग्री जैसे क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग करने में रुचि व्यक्त की।

पीयूष गोयल ने कंपनियों द्वारा दिखाई गई रुचि का स्वागत किया और उन्हें भारत के बुनियादी ढांचे, विमानन तथा स्वास्थ्य सेवा सेक्टरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्रालय ने कहा कि भविष्य की कार्ययोजना के तहत उपयुक्त भारतीय संयुक्त उद्यम साझेदारों की पहचान करने, पायलट परियोजनाओं पर काम करने, लागत-तुलना संबंधी अध्ययन करने और भारतीय संस्थानों के साथ संयुक्त अध्ययन करने की आवश्यकता पर सहमति जताई गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये बैठकें ऐसे समय में हुई हैं, जब भारत और इटली अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को प्रतिवर्ष 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं।

गोयल ने 'एक्स' पर जारी पोस्ट में लिखा, रोम में 'मगाल्डी ग्रीन एनर्जी' की प्रबंध निदेशक सुश्री लेतिजिया मगाल्डी के साथ अच्छी बैठक हुई। हमने स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में भारत-इटली के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इसमें मुख्य रूप से उन्नत थर्मल ऊर्जा भंडारण, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता में सुधार और टिकाऊ तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दीपक राजावत को सीईओ किया नियुक्त



एजेंसी, नई दिल्ली

टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दीपक राजावत को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। एयरलाइन ने बुधवार को कहा कि दीपक राजावत की सीईओ के रूप में नियुक्ति एक दिसंबर से प्रभावी होगी। राजावत वर्तमान में टाटा समूह की इस एयरलाइन में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के पद पर कार्यरत हैं। राजावत को एविएशन और फाइनेंस के क्षेत्र मे दो दशक से अधिक का अनुभव है। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रतिदिन लगभग 585 उड़ानें संचालित करती है, जो 48 घरेलू और 17 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती हैं। एयरलाइन के बेड़े में बोइंग 737 और एयरबस ए320 के कुल 108 विमान हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

एजेंसी, नई दिल्ली

वाणिज्य मंत्रालय ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाना, नए बाजारों तक पहुंच आसान करना है। साथ ही भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को अधिक सहायता देना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि व्यापक भागीदारी और बेहतर सहायता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन की 'निर्यात दिशा' उप-योजना के तहत बाजार पहुंच सहायता, व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन और माल ढुलाई एवं परिवहन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधन के तहत बाजार पहुंच सहायता के तहत खरीदार-विक्रेता बैठक, व्यापार मेलों और व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने के लिए भी हवाई यात्रा के खर्च को वापस लौटाने (रिइम्बर्समेंट)



की पात्रता के लिए निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। इसे पिछले वर्ष के 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों को हवाई यात्रा के खर्च का 95 फीसदी तक और अन्य पात्र निर्यातकों को 80 फीसदी तक राशि वापस की जाएगी। इस बाजार पहुंच सहायता योजना का उद्देश्य खरीदार-विक्रेता बैठकें, विदेशी खरीदार-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेले, प्रदर्शनियां और बाजार तक पहुंच से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए व्यवस्थित सहायता देकर भारतीय निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मजबूत करना है। मंत्रालय ने प्रमाणपत्रों की उस सूची का भी विस्तार किया है, जिनके लिए खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इनकी संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मानकों को पूरा करने के लिए अधिक सहायता उपलब्ध कराना है।

व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन सहायता योजना के तहत एमएसएमई को गुणवत्ता और अनुपालन से जुड़े प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद दी जाती है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकें। इसी तरह, लॉजिस्टिक एवं परिवहन संबंधी सहायता (लिफ्ट) के तहत कम निर्यात वाले जिलों को मिलने वाली सहायता का दायरा मौजूदा 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है।

लाल निशान पर खुला घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 429 अंक टूटा

एजेंसी, नई दिल्ली

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार दो दिन की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली से शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 429 अंक और निफ्टी में 141अंकों की गिरावट है। फिलहाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 429.22 अंक यानी 0.52 फीसदी की गिरावट के साथ 82,102.97 के स्तर पर



कारोबार कर रहा है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 141.25अंक 0.56 टूटकर 25,246.15 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। वहीं, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई का सेंसेक्स 17 नवंबर तक इस महीने में करीब 11 फीसदी और एनएसई का निफ्टी 10 फीसदी से अधिक चढ़ा है। इसके साथ ही एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 सूचकांक बढ़त में कारोबार कर रहे हैं, जबकि चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट में रहे।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी

एजेंसी, नई दिल्ली । भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस अवधि में भारत ने कुल 31.97 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 22.20 अरब डॉलर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस बढ़ोतरी में स्मार्टफोन के साथ-साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का भी बड़ा योगदान रहा है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बनी हुई है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान स्मार्टफोन का निर्यात 35.8 फीसदी बढ़कर 18.17 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 13.38 अरब डॉलर था। हालांकि, कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 60.3 फीसदी से घटकर 56.8 फीसदी रह गई है। इसका कारण यह है कि स्मार्टफोन के अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में ज्यादा तेजी आई है।



- अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने वालों में आमने-सामने लड़ने की हिम्मत नहीं: योगी
- 'रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को अंत समय में मारीच की तरह याद आ रहा राम नाम'
- हैदराबाद से आकर यूपी में मचल रहा एक मौलाना, चुनाव परिणाम के साथ ही तय हो जाएगा हैदराबाद का भाग्यलक्ष्मीपुरम बनना: मुख्यमंत्री

पीड़ित परिवार से मिलेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि झंगहा से गोरखपुर पढ़ने आए किशोर को सपा के रोड शो का शिकार बना दिया गया। माफिया के पोषक मौन रहे और संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने इस घटना पर शोक एवं संवेदना जताते हुए पीड़ित परिवार से मिलने की घोषणा की।

विपक्ष को बताया मारीच

मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्तों को राम अच्छे दिनों में याद आते हैं, लेकिन दुर्जनों को अंत समय में मारीच की तरह राम नाम याद आता है। उन्होंने चुनौती दी कि हिम्मत है तो अयोध्या से नामांकन करें, आमने सामने मुकाबला होगा। कायर पीछे से वार करते हैं।

ओवैसी और इंडी गठबंधन पर निशाना

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, सपा, बसपा व एआईएमआईएम को एक ही थाली के चट्टे-बट्टे बताते हुए कहा कि हैदराबाद से आया मौलाना मचल रहा है। चुनाव परिणाम के साथ ही हैदराबाद का भाग्यलक्ष्मीपुरम बनना तय हो जाएगा।

अखिलेश के रोड शो में किशोर की मौत पर बरसे योगी, बोले

गुंडों को ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के प्रथम वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का किया भूमिपूजन

एजेंसी। गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान एक किशोर की मौत पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे निर्मम हत्या करार दिया है। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि सड़क पर अराजकता फैलाने वाले गुंडों को ढूंढ निकालें और उन्हें ऐसी कठोर सजा दिलाएं जिसे उनकी कई पीढ़ियां याद रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये गुंडे और माफिया डंडे के बल पर ही सीधे होंगे। प्रदेश की सड़कें आम जनमानस के सुगम आवागमन के लिए बनी हैं, न कि सपा और कांग्रेस के गुंडों की अराजकता के लिए। यदि किसी ने दोबारा माफियागिरी दिखाने का दुस्साहस किया, तो उसे मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के भारीवैसी में उत्तर प्रदेश के प्रथम वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के भूमिपूजन तथा 792 करोड़ रुपये से अधिक की 55 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से विश्वविद्यालय का भूमिपूजन किया और कल्पवृक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।



अगले सत्र से शुरू होंगी कक्षाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले सत्र से वैकल्पिक स्थान पर वानिकी विश्वविद्यालय की कक्षाएं शुरू होंगी और तय समय सीमा में भवन बनेगा। यहां स्नातक, परास्नातक, पीएचडी व डिप्लोमा स्तर के सिल्वीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री व औद्यानिकी पाठ्यक्रम चलेंगे।

साढ़े नौ वर्ष में 280 करोड़ वृक्षारोपण

वैदिक सूत्र 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण दोहन से आपदाएं आती हैं। 12 जुलाई 2026 को एक दिन में 35 करोड़ व साढ़े नौ वर्ष में 280 करोड़ पौधे लगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'मन की बात' में भी किया।

'सपा सरकार में अपराध का बोलबाला था'

सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि अखिलेश यादव की रैली में भाजपा कार्यकर्ता के 12 वर्षीय पुत्र को कुचल दिया गया। सपा सरकार में अपराध व इंसेफेलाइटिस का बोलबाला था, जबकि आज जमीनों पर कब्जे का डर खत्म हुआ है।

किसानों को विशेष पैकेज, एग्रोफॉरेस्ट्री नियम होंगे सरल

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को गोरखपुर में 500 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है और जल्द ही अलग से विशेष पैकेज मिलेगा। एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन होगा।

जनगणना-2027: सीएम ने भरा ऑनलाइन स्व-गणना फॉर्म, प्रदेशवासियों से भागीदारी की अपील



एजेंसी। नई दिल्ली

जनगणना 2027 के दूसरे चरण के अंतर्गत जारी स्व-गणना अभियान में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की। मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक चलने वाली ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया में सभी नागरिकों से हिस्सेदारी की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा उपस्थित रहीं।

पूर्ण किया सभी कॉलम

मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने आवास पर प्रदेश में जारी ऑनलाइन जनगणना के दूसरे चरण के अंतर्गत स्व-गणना (सेल्फ एनुमेरेशन) का ऑनलाइन फॉर्म भरा। मुख्यमंत्री ने स्व-गणना पोर्टल पर जाकर समस्त प्रश्नावली (40 प्रश्न) के सापेक्ष अपनी जानकारी दर्ज की। उन्होंने सभी कॉलम को पूर्ण किया। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील की।

एक्स पर लिखा- स्व-गणना राष्ट्रीय कार्य है

इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा, स्व-गणना राष्ट्रीय कार्य है। आज गोरखपुर में ''जनगणना-2027'' के अंतर्गत अपनी स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण की। जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि हर नागरिक की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की योजनाओं का आधार है। सभी सम्मानित उत्तर प्रदेश वासियों से अपील है कि इसमें बढ़-चढ़कर भाग लें और विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।



कल लखनऊ आएंगे पीएम मोदी, अलर्ट पर आई सुरक्षा व्यवस्था

लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को राजधानी आएंगे। वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रस्तावित कौशल भारत, कुशल भारत के अंतर्गत पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शनिवार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक यातायात परिवर्तित रहेगा। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस स्कूली वाहन, शव वाहन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को निकलवाएगी। डिगडिगा (लोहिया पार्क) चौराहा से आने वाला सामान्य यातायात गोमतीनगर नया ओवरब्रिज पर नहीं जा सकेगा। यह पिकप तिराहा होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेगा। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान तिराहा से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर यातायात नहीं जा सकेगा। लोहिया अस्पताल जाने वाले व्यक्तियों के वाहन पिकप ढाल से उतरकर लोहिया अस्पताल से पहले तिराहा से गाएं मुड़कर अस्पताल के गेट नंबर एक से प्रवेश करेंगे। पिकप ओवरब्रिज के ऊपर दोराहा से सामान्य यातायात पिकप पुल ढाल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर नहीं जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया साफ: रेस्टोरेंट में खाने के बिल में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं, यह आदेश का उल्लंघन

एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूलने पर रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। यह स्पष्टीकरण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के बयान के बाद आया। शर्मा ने बताया कि कुछ रेस्टोरेंट में अभी भी सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है। यह एकल न्यायाधीश के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसने सर्विस चार्ज पर रोक लगाई थी।

रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से मना किया

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह बात कही।

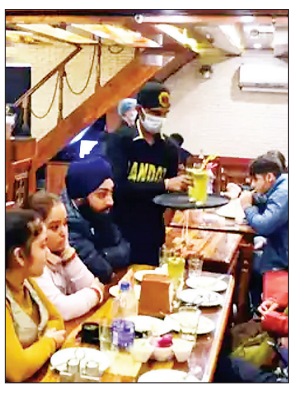

पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च, 2025 के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। न्यायाधीश सांब्रे ने कहा कि कार्रवाई करना आपका काम है। हमने कोई अंतरिम प्रार्थना मंजूर नहीं की है। अदालत नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने गुरुवार को इन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।

एकल न्यायाधीश का फैसला

एकल न्यायाधीश ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों को सही ठहराया था। इन दिशानिर्देशों में कहा गया था कि होटल और रेस्टोरेंट बिलों में सर्विस चार्ज अपने आप नहीं जोड़ सकते। अदालत ने पाया कि सर्विस चार्ज सीधे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक होना चाहिए। ग्राहकों को भुगतान के लिए मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा है। अदालत ने सीसीपीए के वैधानिक अधिकार की भी पुष्टि की।

भ्रामक शब्दों पर रोक

एकल न्यायाधीश ने 'सर्विस चार्ज' शब्द के भ्रामक उपयोग पर भी रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं को सरकारी कर समझने के लिए गुमराह कर सकता है। रेस्टोरेंट को ऐसे शुल्कों के लिए स्पष्ट शब्दों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। जैसे 'स्वैच्छिक योगदान' या 'कर्मचारी कल्याण कोष' जैसे शब्द इस्तेमाल करने को कहा गया। रेस्टोरेंट को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि बिलों में ऐसे शुल्क अपने आप न जुड़ें।

आज फिर घुटेगा दिल्ली का दम: एक दिन में एक्यूआई 48 अंक बढ़कर 280 हुआ दर्ज, आने वाले दिनों में राहत के नहीं आसार

एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली में बीते कई दिन से चल रही तेज हवाओं ने प्रदूषण से कुछ राहत जरूर दिलाई है, लेकिन जहरीली हवा का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। बयार भले ही खराब श्रेणी में हो लेकिन, इससे अभी भी दिल्लीवासियों की सांसों पर संकट बरकरार है। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का अनुमान है कि शुक्रवार को हवा एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। ऐसे में लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर, बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 280 दर्ज हुआ, जोकि खराब श्रेणी में है। यह बुधवार की तुलना में 48 सूचकांक अधिक है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के अनुसार, बृहस्पतिवार को औसतन पांच किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से हवा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर से चलीं। वहीं, शुक्रवार को हवा उत्तर-पूर्व से पांच किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चलने का अनुमान है। साथ ही, शनिवार को हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चल सकती है। इस दौरान हवा की गति 10 किमी प्रतिघंटा रहने के आसार है। सीपीसबी के अनुसार, हवा में मौजूद हानिकारक पीएम 2.5 कणों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

15 इलाकों में प्रदूषण 300 के पार

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। शहर के कई इलाकों में हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 15 इलाकों में पीएम2.5 का स्तर 300 या उससे अधिक दर्ज किया गया। इससे साफ है कि राजधानी की हवा लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है।

अब बार-बार नहीं बनवाना होगा पीयूसी, बीएस-6 गाड़ियों के लिए बदले नियम

नई निजी गाड़ियों को तीन साल तक मिलेगी प्रदूषण प्रमाणपत्र से राहत, वाहन की उम्र के हिसाब से तय हुई नवीनीकरण की अवधि

एजेंसी। नई दिल्ली

नई दिल्ली। वाहन चालकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) बनवाने को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब नई बीएस-6 निजी गाड़ियों के मालिकों को हर छह महीने या साल में पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी। छह साल तक पुरानी बीएस-6 निजी गाड़ियों के लिए यह प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रहेगा। हालांकि, पुराने वाहनों के लिए पहले की तरह कम अवधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा। मंत्रालय ने 13 नवंबर को नए नियम अधिसूचित किए हैं। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये नियम लागू हो गए हैं। सरकार ने निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए उनकी उम्र के आधार पर पीयूसी प्रमाणपत्र की अलग-अलग वैधता अवधि निर्धारित की है।



13 नवंबर से लागू हुए नए नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (16वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता में यह बदलाव किया है। यह संशोधन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत किया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए नियम प्रभावी हो गए हैं। हालांकि, नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए पीयूसी प्रमाणपत्रों की वैधता अपने आप नहीं बदलेगी। उन पर संशोधित समयसीमा तभी लागू होगी, जब नए नियम लागू होने के बाद पहली बार प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराया जाएगा।

नई बीएस-6 निजी गाड़ियों के लिए क्या बदला?

सरकार ने निजी बीएस-6 वाहनों की उम्र के हिसाब से पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता तय की है। अब वाहन जितना पुराना होगा, उतनी जल्दी प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा।

- छह साल तक पुराने बीएस-6 निजी वाहनों का पीयूसी प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रहेगा।
- छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए हर साल नवीनीकरण कराना होगा।
- 10 साल से अधिक पुराने बीएस-6 निजी वाहनों के लिए हर छह महीने में पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाना जरूरी होगा।

व्यावसायिक वाहनों के लिए क्या हैं नियम?

सरकार ने बीएस-6 मानक वाले व्यावसायिक और परिवहन वाहनों के लिए भी पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि बढ़ाई है। हालांकि, इन वाहनों के लिए निजी गाड़ियों की तुलना में अलग समयसीमा तय की गई है।

- छह साल तक पुराने बीएस-6 परिवहन वाहनों का प्रमाणपत्र दो साल तक वैध रहेगा।
- छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों को हर साल प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा।
- 10 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के लिए हर छह महीने में पीयूसी प्रमाणपत्र रिन्यू कराना जरूरी होगा।

पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराने पर क्या होगा?

नए नियमों में प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की तारीख को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। अगर कोई वाहन मालिक मौजूदा पीयूसी सर्टिफिकेट की समयसीमा खत्म होने से पहले उसे रिन्यू कराता है, तो नई वैधता की शुरुआत अलग तरीके से तय होगी। अगर प्रमाणपत्र की समयसीमा खत्म होने से पहले के आखिरी 10 दिनों में नवीनीकरण कराया जाता है, तो नए प्रमाणपत्र की वैधता पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से शुरू होगी। अगर प्रमाणपत्र एक्सपायर होने के बाद नवीनीकरण कराया जाता है, तो नए प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण की तारीख से शुरू होगी।

नए नियम कब से लागू हुए और पुराने सर्टिफिकेट पर क्या असर होगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (16वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत यह बदलाव अधिसूचित किया है। यह संशोधन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत किया गया है। नियम राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गए। हालांकि, नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए पीयूसी प्रमाणपत्रों की वैधता अपने आप नहीं बदलेगी। उन पर संशोधित समयसीमा तभी लागू होगी, जब नए नियम लागू होने के बाद पहली बार उनका नवीनीकरण कराया जाएगा।

बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों को कितनी राहत?

सरकार ने पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि में कोई बड़ी छूट नहीं दी है। इन वाहनों के लिए पहले की तरह ही कम अवधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा।

- बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 वाहनों का पीयूसी प्रमाणपत्र तीन महीने तक वैध रहेगा।
- बीएस-4 वाहनों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता छह महीने होगी।

एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराने पर क्या होगा?

नए नियमों में पीयूसी प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की तारीख को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। यदि वाहन मालिक मौजूदा प्रमाणपत्र की समयसीमा खत्म होने से पहले नया प्रमाणपत्र बनवाता है, तो उसकी वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि नवीनीकरण कब कराया गया है।

- यदि प्रमाणपत्र की समयसीमा खत्म होने से पहले के आखिरी 10 दिनों में नवीनीकरण कराया जाता है, तो नए प्रमाणपत्र की वैधता पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से शुरू होगी।
- यदि प्रमाणपत्र की समयसीमा समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराया जाता है, तो नए प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण की तारीख से शुरू होगी।

THE UNCOVERED UPDATE
सच जो छुपा था, अब सामने है

हिन्दी समाचार पत्र

राजस्थान अपडेट

धरोहर, विकास और जनहित की खबर | Digital Edition | RJHIN/25/A4779

शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026

टोक्यो में चौथी भारत-जापान 2 प्लस 2 वार्ता

समुद्र से आसमान तक भारत-जापान की साझेदारी, रक्षा तकनीक में भी साथ आएंगे दोनों देश



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत-जापान रक्षा सहयोग को नई रफ्तार देने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक तक मिलकर काम करेंगे। टोक्यो में चौथी भारत-जापान 2 प्लस 2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अहम बातें साझा की हैं। दोनों देश समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में आयोजित वार्ता के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और जापान एशिया के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं और विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। ऐसे में मौजूदा वर्ष दोनों देशों के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि वे इस ऐतिहासिक अवसर के जश्न की तैयारियों की नींव रख रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में हुए सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा-पत्र के अनुरूप रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत में आयोजित वीर गार्जियन-26 हवाई अभ्यास में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी का स्वागत किया।

एग्रीगेटर नीति लागू करने में राजस्थान देश में प्रथम, नितिन गडकरी ने की सराहना

चालक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा,डिजिटल पंजीकरण और नियामकीय जवाबदेही के प्रावधानों को बताया महत्वपूर्ण



नई दिल्ली/जयपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में लागू करने की पहल की सराहना करते हुए राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया है, जिसने इन दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू किया है। उन्होंने अन्य राज्यों से भी राजस्थान की तर्ज पर एग्रीगेटर नीति को अपनाने का आह्वान किया। श्री गडकरी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'RIDE: A Showcase of Aggregator and Delivery Services' कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया, जिसने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया है। कार्यक्रम में देश में एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों, चालक कल्याण तथा सुरक्षित और समावेशी परिवहन व्यवस्था के विकास पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 को जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान ने नियम बनाकर उन्हें लागू किया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन दिशा-



निर्देशों को आंशिक रूप से लागू किया गया है। राजस्थान की इस पहल से अन्य राज्यों को भी एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन के लिए दिशा मिलेगी।

प्रमुख शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने दिया राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का सुझाव

कार्यक्रम में राजस्थान की ओर से प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, श्री भवानी सिंह देथा ने राज्य में एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन एवं डिजिटल पंजीकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से एग्रीगेटर कंपनियों के पंजीकरण, लाइसेंस, वाहनों के पंजीयन, चालक संबंधी व्यवस्थाओं तथा नियामकीय अनुपालना के लिए स्पष्ट व्यवस्था विकसित की गई है। कार्यक्रम में उप परवहन आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह राठोड व अलवर आरटीओ श्री रविन्द्र सिंह भी शामिल हुए ।

राजस्थान ने दिसंबर 2025 में ही लागू किए एग्रीगेटर नियम

श्री भवानी सिंह देथा ने बताया की राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुरूप 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों के माध्यम से राज्य में एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के नियमन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। राजस्थान की नीति की विशेषता यह है कि इसमें केवल यात्री परिवहन सेवाओं को ही नहीं, बल्कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को भी नियामकीय दायरे में शामिल किया गया है।

सियोल घोषणापत्र पर मुख्य सचिव ने किए हस्ताक्षर

आईआईएएस अध्यक्ष के रूप में बेहतर जनजीवन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की साझा प्रतिबद्धता जताई

सहयोग आधारित शासन, सामाजिक नवाचार और संसाधनों के जवाबदेह उपयोग पर जोर



सियोल/जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के अध्यक्ष के रूप में गुरुवार को सियोल घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। कोरिया गणराज्य के सियोल में आयोजित आईआईएएस 2026 सम्मेलन के दौरान उन्होंने लोक प्रशासन संस्थाओं और भागीदार संगठनों के प्रमुखों के साथ आर्थिक विकास को लोगों के जीवन में स्थायी सुधार से जोड़ने की साझा प्रतिबद्धता जताई। घोषणापत्र की पांच प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सरकार की सक्रिय भूमिका के साथ उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने नीति निर्माण में नागरिकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों की सार्थक भागीदारी पर भी जोर दिया। सामाजिक नवाचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक समस्याओं के सफल समाधानों की पहचान कर उन्हें व्यापक स्तर पर अपनाने की जरूरत है। कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार से इस प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। टेक्नोलॉजी और डेटा का जिम्मेदारी से उपयोग भी इन प्रयासों को मजबूत बनाने में सहायक होगा।

न्यूज़ ब्रीफ

अजमेर उत्तर में दिसम्बर अंत तक पूरा होगा 39 सड़कों का निर्माण कार्य: देवनानी

जनाना अस्पताल में कॉटेज निर्माण कार्य जनवरी तक पूरा करने के निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सड़क तंत्र को मजबूत बनाने के लिए दिसम्बर माह के अंत तक 39 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में 23 विशिष्टताओं में 209 सहायक आचार्यों के नियुक्ति आदेश जारी

न्यायालय से रोक हटने के बाद विभाग ने आगे बढ़ाई भर्ती प्रक्रिया

जनरल सर्जरी में 41, स्त्री एवं प्रसूति रोग में 39 तथा जनरल मेडिसिन में 31 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति

जयपुर(नि.सं.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में फैकल्टी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 23 विशिष्टताओं में 209 चयनित सहायक आचार्यों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। खींवसर ने बताया कि वर्ष 2021 में सहायक आचार्य भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी। गत 6 नवम्बर 2026 को न्यायालय से रोक हटने के बाद विभाग ने आवश्यक कार्यवाही पूरी कर 18 नवम्बर को 209 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में 'लोकमंथन-2026' में दिया कुमारी ने लिया भाग

जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में 'लोकमंथन-2026' की स्वागत समिति की बैठक में सहभागिता कर लोकमंथन के सफल एवं भव्य आयोजन की तैयारियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तथा अन्य विभिन्न विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, राष्ट्रबोध और वैचारिक विमर्श को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा।



हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण

शासन सचिव, कार्मिक विभाग ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण

परिवादों का विषयवार वर्गीकरण कर प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण कर यहां संचालित व्यवस्थाओं एवं परिवादों के निस्तारण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाले परिवादों की प्रकृति, वर्गीकरण एवं निस्तारण की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। सिंह ने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से विभाग को प्राप्त होने वाले सभी प्रकरण अनिवार्य रूप से शिकायत की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि इनमें नीतिगत विषयों (Policy Matters), व्यक्तिगत मामलों एवं विभिन्न मांगों से संबंधित प्रकरण भी शामिल होते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का उनकी प्रकृति के अनुरूप पृथक-पृथक वर्गीकरण किया जाए तथा विषयों का समुचित मॉडरेशन सुनिश्चित किया जाए। इससे प्रकरणों का सही विश्लेषण संभव हो सकेगा और प्रत्येक





प्रकरण के अनुरूप समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से जयपुर निवासी परिवादी संजीव से भी संवाद किया। परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में आईपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) प्रस्तुत नहीं कर पाने की समस्या से अवगत कराने पर श्रीमती सिंह ने उन्हें आईपीआर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया समझाते हुए इसकी अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार प्रत्येक कार्मिक के लिए निर्धारित समयावधि में आईपीआर प्रस्तुत करना आवश्यक है। श्रीमती सिंह ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने शिकायतों के विश्लेषण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए विकसित सम्पर्क एआई प्रणाली की भी प्रशंसा की।

राजनीतिक तनाव

बांग्लादेश में हसीना की वापसी से पहले सरकार सख्तः अवामी लीग के नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी

सभी जिलों में बॉर्डर गार्ड तैनात करने का प्लान

ढाका। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले सरकार अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दैनिक भास्कर के हाथ लगी गृह मंत्रालय की 16 नवंबर की गोपनीय रिपोर्ट में पार्टी के सक्रिय नेताओं के खिलाफ पहले ही कानूनी कार्रवाई करने, उससे जुड़े संगठनों पर नजर रखने और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में 20 नवंबर से देश के सभी जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) तैनात करने का प्लान भी है। इसमें कहा गया है कि शेख हसीना दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौट सकती हैं। उनकी वापसी से



देश में राजनीतिक तनाव बढ़ने और हिंसा होने का खतरा बताया गया है।

अवामी लीग के नेताओं पर पहले कार्रवाई की तैयारी

रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बाद अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता फिर सक्रिय हो सकते हैं। इससे विरोधी दलों के साथ टकराव और राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को पहले से तैयार रहने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने अवामी लीग के सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान कर उनके खिलाफ पहले ही कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की है। खास तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई है।



ओडिशा में चक्रवात अकवान का खतरा, अब तक 72 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा में चक्रवात अकवान के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बचाव और राहत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब तक करीब 72 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। चक्रवात के शुक्रवार दोपहर उत्तर आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकराने की आशंका जताई गई है।

ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने गुरुवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य सरकार पिछले कई दिनों से चक्रवात की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पहले चक्रवात का रुख किसी अन्य दिशा में था, लेकिन बुधवार से इसने अपना रास्ता बदल लिया और ओडिशा की ओर बढ़ने लगा।



दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिकाएं स्वीकार कीं, सर्विस चार्ज पर अंतरिम राहत नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूलने के अधिकार की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। अदालत ने गुरुवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अपीलें स्वीकार कर लीं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने फिलहाल रेस्टोरेंट संचालकों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि रेस्टोरेंट कर्मचारियों को टिप देना या नहीं देना पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।

भारत फूड एंड एग्रो @ 2047 कॉन्क्लेव 21 नवंबर को दिल्ली में, खाद्य एवं कृषि क्षेत्र के उद्यमी जुटेंगे भारत मंडपम में

नई दिल्ली। देशभर में एमएसएमई सेक्टर के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण के लिए बीते तीन दशकों से कार्यरत संगठन लघु उद्योग भारती की ओर से 21 नवम्बर को दिल्ली में खाद्य एवं कृषि विषयक नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित किया जायेगा। ये जानकारी संगठन के खाद्य एवं कृषि उत्पाद समूह के राष्ट्रीय सह-समन्वयक आशीष देवड़ा ने आज लघु उद्योग भारती के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत-2047 की संकल्पना को साकार करने में फूड एवं एग्रो सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी जिसमें कृषि उत्पादों का बड़े स्तर पर मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) का कार्य किया जायेगा। देवड़ा ने बताया कि हर वर्ष देश में करीब 90 हजार करोड़ की कृषि पैदावार खराब हो जाती है जिसमें हॉर्टिकल्चर उत्पाद- फल और सब्जियां शामिल हैं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने इस



बात पर भी जोर दिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) फूड एवं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ा अवसर है। उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर का फायदा उठाने के लिए कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन को अत्यंत आवश्यक बताया। देवड़ा ने बताया कि फसल कटाई के बाद होने वाले संभावित नुकसान को सीमित करने वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन की व्यवस्था को और गतिशील बनाने की जरूरत है।

एमएसएमई इकाइयों को विदेशों में व्यापार करने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को एक पासपोर्ट की दर्जा देना होगा न कि उसे किसी तरह का भार समझा जाये।

एमओयू **जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के बीच एमओयू**

विद्यार्थियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के बीच हुआ एमओयू

विद्यार्थियों को सरकारी संचार व्यवस्था, डिजिटल मीडिया और जनसंपर्क के क्षेत्र में इंटर्नशिप, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का मिलेगा अवसर

जयपुर(नि.सं.)। राज्य सरकार के कौशल विकास मिशन की दिशा में कदम उठाते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के बीच एमओयू किया गया। भावी मीडिया पेशेवरों के कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में यह



पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव राकेश शर्मा और स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के निदेशक डॉ. मौलिक शाह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य मीडिया के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना तथा उन्हें सरकारी संचार एवं जनसंपर्क की कार्यप्रणाली से परिचित कराना है। एमओयू के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, शैक्षणिक भ्रमण, विशेषज्ञों के साथ संवाद और व्यावसायिक मार्गदर्शन के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विभाग की प्रकाशन गतिविधियों, डिजिटल संचार, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, जनजागरूकता अभियानों तथा जनसंपर्क की विभिन्न कार्यप्रणालियों को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थियों में मीडिया उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने के साथ ही जिम्मेदार जनसंचार की समझ को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त श्री राकेश शर्मा ने कहा, ÷सूचना एवं जनसंपर्क विभाग युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों को कक्षाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वामी और प्रकाशक बुधमती गोस्वामी एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 10 MA, आईजी नगर, जगतपुरा,जयपुर, राजस्थान - 302017 से प्रकाशित किया। प्रधान संपादकः बुधमती गोस्वामी एवं संपादकः रमाकान्त गोस्वामी, उप संपादक - मोनिका शर्मा, पीआरजीआई नं. RJHIN/25/A 4779 ब्रांच ऑफिसः 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल आईडीः editor.the uncoveredupdate@gmail.com, वेबसाइटः www.theuncoveredupdate.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तदायी), किसी भी वाद-विवाद से निपटने के लिए न्यायालय जयपुर मान्य होगा।